



उत्तराखण्ड शासन

उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड

वर्ष 2012–13
की
कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका
तथा
वर्ष 2013–14 का

आय–व्ययक

प्राक्कथन

उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ एवं बेहतर बनाने की समग्र एवं अनवरत विकास यात्रा में वित्तीय वर्ष 2012–13 में विगत वर्ष के आय व्ययक का कार्य पूर्ति दिग्दर्शक प्रस्तुत किया जा रहा है।

राज्य गठन के पश्चात उच्च शिक्षा में पर्याप्त विकास एवं विस्तार हुआ है किन्तु वैश्वीकरण के इस स्पर्धात्मक युग में उच्च शिक्षा भी सुधारों की प्रक्रिया से गुजर रही है, जिसके अन्तर्गत गुणवत्ता सुनिश्चयीकरण के साथ–साथ उच्च शिक्षा की पहुँच को विस्तृत करना सर्वोच्च प्राथमिकता बन गयी है। इस दृष्टि से सुव्यवस्था एवं गुणवत्ता के मानकों के अनुसार महाविद्यालयों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था करना अपरिहार्य हो गया है। फलस्वरूप आगामी वर्षों में संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था के साथ–साथ उनका अनुकूलतम उपयोग भी आवश्यक होगा।

आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास भी है कि वर्ष 2012–13 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक, उच्च शिक्षा निदेशालय की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की प्रक्रिया में न केवल प्राविधानित धनराशि के समुचित उपयोग एवं निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगा वरन् समस्त कार्मिकों एवं अन्य हितधारकों की क्रियाओं को आलोकित करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी सिद्ध होगा।

प्रमुख सचिव
उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

उच्च शिक्षा विभाग की संदृष्टि (VISION)

उत्तराखण्ड को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करना, जो अपने निवासियों हेतु अत्यन्त उच्च स्तर की शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रवर्तन, कला, विज्ञान एवं संस्कृति का संपोषण, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के उच्चतम उन्नयन का सुनिश्चयन, प्रत्येक की आवश्यकतानुसार रोजगारपरक कौशलों में समुचित प्रशिक्षण के द्वारा निर्धनता एवं बेरोजगारी का उन्मूलन तथा राज्य के समेकित विकास में उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं शोध केन्द्रों की संवृद्धि और विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग हेतु एक उचित परिवेश एवं अधःसंरचना का सृजन करे।

उच्च शिक्षा विभाग का ध्येय (MISSION)

- माध्यमिक शिक्षा की प्राप्ति के उपरान्त युवाओं को आवश्यकता एवं मांग के अनुसार गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, उन्हें सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना तथा शोधपरक विकास का प्रवर्तन करना, जिससे वह वैशिक चुनौतियों का सामना कर सके।
- पारम्परिक शिक्षा के साथ-साथ पेशेवर एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित करना।
- उत्तराखण्ड को ज्ञान के केन्द्र के रूप में विकसित कर एक जागृत व समृद्ध राज्य बनाना।
- कला, संस्कृति एवं विज्ञान का विकास कर युवावर्ग के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना।

उच्च शिक्षा विभाग के उद्देश्य (GOALS)

- 16 वर्ष तक की उम्र के समस्त बालक एवं बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक दायित्व के अनुक्रम में गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा को सुनिश्चित करना।
- नवोदित ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिये शिक्षित एवं कौशल युक्त प्रशिक्षित मानव संपदा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना।
- राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिये रोजगारपरक कौशलों में सुनिश्चित वृद्धि तथा प्रौढ़ एवं रोजगार प्राप्त कार्मिकों के कौशल विकास में अभिवृद्धि हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा एवं शोध हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में निजी विनियोग को आकर्षित करना।

पृष्ठभूमि (BACKGROUND)

विकास एवं प्रगति के लिए ज्ञान एवं कौशल के व्यापक जन संचार के माध्यम से मानव संसाधनों का सशक्तीकरण परम आवश्यक है। शिक्षा, ज्ञान एवं कौशल के द्वारा व्यक्तियों को सक्षम बनाकर उन्हें उत्पादन, रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए योग्य बनाती है। इस कारण शिक्षा में होने वाला व्यय, विनियोग (Investment) के सदृश समझा जाता है।

सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक मुद्दों पर मानवीय संवेदनाओं को जागृत कर मानवता को प्रबोधित कर व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध कराने वाली उच्च शिक्षा, वैश्वीकरण एवं उदारीकरण से ओत—प्रोत वर्तमान तीव्र परिवर्तनशील परिवेश में नवीन अवसरों एवं चुनौतियों (Opportunities and Challenges) के ऐसे दौर से गुजर रही है, जिसमें एक ओर उच्च शिक्षा के प्रति बढ़ती जनधेतनाओं एवं आकांक्षाओं से वर्तमान संरचना पर बढ़ते दबाव का सामना करना है, तो वही दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एवं गुणवत्ता के विश्वव्यापी वातावरण में ज्ञान के सृजन के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ एवं क्षमताएँ अर्जित करने के अवसरों को प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है। विगत पंचवर्षीय योजनाओं में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है किन्तु साथ ही उच्च शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था उच्च शिक्षा की पहुँच (Access), समता (Equity), प्रासंगिकता (Relevance), सुशासन (Good Governance) जैसे तत्वों पर ध्यान केन्द्रित करने पर जोर दे रही है।

उत्तराखण्ड को ज्ञान प्रदेश (Knowledge State) के रूप में प्रतिष्ठित करने की संदृष्टि को साकार करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की बहुआयामी भूमिका मुख्यतः निम्नांकित क्षेत्रों में प्रमुख हो गयी है :—

- नवीन ज्ञान का सुजन।
- दक्षताओं एवं नवीन क्षमताओं का अर्जन।
- प्रभावशाली अध्यापन, शोध एवं प्रसार गतिविधियों के माध्यम से प्रबुद्ध मानवीय सम्पदा के व्यापक समूह को तैयार करना।

उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा : उद्भव एवं विकास

उच्च शिक्षा के प्रति उत्तराखण्ड के निवासियों का प्रारम्भ से ही रुझान रहा है, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्डवासियों द्वारा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति, नौकरशाही, सेना, विज्ञान एवं तकनीकी, जनसंचार, शोध इत्यादि क्षेत्रों में गरिमामय उपस्थिति एवं योगदान में प्रतिबिम्बित होती है। प्रदेश में ही उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों— सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा इत्यादि में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना स्वातन्त्र्योत्तर काल में हुई, किन्तु उच्च शिक्षा का वास्तविक प्रसार सत्तर के दशक से प्रारम्भ हुआ, जब असेवित एवं दूर दराज के क्षेत्रों में महाविद्यालयों की स्थापना बड़े पैमाने पर हुई ताकि कमज़ोर आर्थिक स्थिति एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों में उच्च शिक्षा के अवसरों की पहुँच सामान्य जनता तक सुलभ बनाई जा सके। राज्य गठन से पूर्व महाविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी तथा उच्च शिक्षा की वर्तमान संरचना राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न नवीन चुनौतियों एवं अवसरों के साथ समायोजन करने में असमर्थ थी। राज्य गठन के पश्चात शासन द्वारा उच्च शिक्षा के प्रसार तथा गुणवत्ता के सुनिश्चयीकरण हेतु बजट में निरन्तर वृद्धि की गई तथा उच्च शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी तथा नवोन्मेषों का उपयोग प्रारम्भ हुआ।

प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास एवं प्रगति को निम्नांकित 3 भागों में वर्णीकृत किया जा सकता हैः—

उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा की प्रगति

(क) प्रवर्तन एवं प्रारम्भिक विकास की अवस्था : (1970 से पूर्व)

- डी०ए०वी० अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना (1946)
- रुड़की इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना (1949)
- प्रथम शासकीय महाविद्यालय के रूप में डी०ए०स०वी० महाविद्यालय, नैनीताल की स्थापना (1951)
- अल्मोड़ा कालेज अल्मोड़ा की स्थापना (1954)
- एम०के०पी० कालेज देहरादून की स्थापना (1958)
- पं० गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर की स्थापना (1960)

(ख) प्रसार एवं समृद्धि की अवस्था : (राज्य गठन से पूर्व)

- सत्तर के दशक में 15, अस्सी के दशक में 05 तथा नब्बे के दशक में 09 शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना, तथा 03 अशासकीय महाविद्यालयों – हल्द्वानी, अल्मोड़ा एवं काशीपुर के प्रान्तीयकरण से शासकीय महाविद्यालयों की संख्या 34 हुई।
- संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) के कार्यालय की हल्द्वानी में स्थापना (1996)
- कुमार्यू गढ़वाल तथा दो डीस्ट्रिक्ट विश्वविद्यालयों (गुरुकुल कांगड़ी व एफ०आर० आई०) की स्थापना

(ग) तीव्र प्रसार, समृद्धि तथा गुणवत्ता सुनिश्चयीकरण के प्रति चेतना की अवस्था : (राज्य गठन के पश्चात)

- उच्च शिक्षा के संवर्द्धन, आधुनिकीकरण, विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड की हल्द्वानी में स्थापना (2001)
- शासन स्तर पर समन्वयकारी भूमिका के निर्वहन एवं अशासकीय महाविद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु देहरादून में उच्च शिक्षा निदेशक (शिविर कार्यालय) की 2001 में स्थापना।
- स्ववित्त पोषित महाविद्यालय देवप्रयाग का प्रान्तीयकरण तथा चन्द्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय, काशीपुर अनुदान सूची में सम्मिलित। वर्ष 2001–02 में 15, 2003–04 में 01, 2004–05 में 02 तथा 2005–06 में 02 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना।
- वर्ष 2006–07 में 10, वर्ष 2008–09 में 02, वर्ष 2009–10 में 02, एवं वर्ष 2010–11 में 01, नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना।

उत्तराखण्ड में स्थापित विभिन्न विश्वविद्यालय व राष्ट्रीय महत्व के संस्थान :

(अ) केन्द्रीय विश्वविद्यालय:

क्र०सं०	विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
1	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)।	1973 (15 जनवरी, 2009 से केन्द्रीय विवि०)

(ब) राज्य विश्वविद्यालय :

क्र०सं०	विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
1	गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर (उधमसिंह नगर)	1960
2	कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।	1973
3	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।	2005
4	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।	2005
5	दून विश्वविद्यालय, देहरादून।	2005
6	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।	2005
7	श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय चम्बा (ठिहरी)	2011
8	उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विवि० भवाली, नैनीताल	2011
9	उत्तराखण्ड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार (पौड़ी)	2011
10	उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून	2011

(स) निजी विश्वविद्यालय :

क्र०सं०	विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
1	देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शान्तिकुंज, हरिद्वार।	2002
2	पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, देहरादून।	2003
3	हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय, देहरादून।	2003
4	इकफाई विश्वविद्यालय, देहरादून।	2003
5	पतञ्जली विश्वविद्यालय, हरिद्वार।	2007
6	उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विवि० देहरादून।	2011

(द) डीम्ड विश्वविद्यालय :

क्र०सं०	विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
1	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।	1902
2	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून।	1991
3	हिमालयन इंस्टीट्यूट, देहरादून।	2007
4	ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, देहरादून	2008

(य) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान

क्र०सं०	संस्थान	स्थापना वर्ष
1	आई०आई०टी० रुड़की	2001
2	भारतीय प्रबन्धन संस्थान काशीपुर (उधमसिंह नगर)	2011
3	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर (पौड़ी)	2011

उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत केवल चार राज्य विश्वविद्यालय (कुमाऊँ मुक्त, दून तथा श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय) संचालित हैं तथा पॉच निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किये जा चुके हैं।

उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात विभाग की वर्षावार उपलब्धियाँ

2001–2002

- प्रदेश का सर्वप्रथम शासकीय विधि महाविद्यालय, गोपेश्वर में स्थापित किये जाने का निर्णय।
- प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय, देवप्रयाग का प्रान्तीयकरण।
- शिक्षकों एवं प्राचार्यों के 12 तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 17 पदों का सृजन।
- शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा में नामाकन 76590 जिसमें 38269 छात्रायें सम्मिलित।
- प्रदेश के दूर-दराज के असेवित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुँच सुलभ कराने के लिये 33 नये महाविद्यालय स्थापित।
- उच्च शिक्षा पर योजनागत एवं गैर योजनागत वास्तविक व्यय रु0 3490.13 लाख।

2002–2003

- शिक्षकों एवं प्राचार्यों के 08 तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 13 पदों का सृजन।
- उच्च शिक्षा में नामांकित विधार्थियों की संख्या 82426 जिसमें 43157 छात्रायें सम्मिलित।
- उच्च शिक्षा पर योजनागत एवं गैर योजनागत वास्तविक व्यय रु0 4117.64 लाख।

2003–2004

- वर्ष 2001–02 में स्थापित 15 महाविद्यालयों में प्राचार्यों एवं शिक्षकों के 106 तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 124 पदों का सृजन।
- उच्च शिक्षा में नामांकित विधार्थियों की संख्या 83781, जिसमें 44722 छात्रायें सम्मिलित।
- प्रत्येक जनपद में एक महाविद्यालय को आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित किये जाने की योजना प्रारम्भ। पिथौरागढ़, गोपेश्वर एवं ऋषिकेश महाविद्यालय आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु चयनित। इन महाविद्यालयों में उच्च स्तरीय प्रयोगशालाओं शिक्षण कक्षों जिमनेजियम, छात्रावास, पुस्तकों एवं फर्नीचर तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु अनुदान स्वीकृत।
- नैक द्वारा प्रायोजित एक दिवसीय गुणवत्ता संवर्द्धन कार्यशाला आयोजित।
- शिखर परियोजना के अन्तर्गत 500 से अधिक छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों में शिक्षा प्रदाताओं द्वारा तथा 500 से कम छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों में शासन द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना प्रारम्भ।
- बेरीनाग, लोहाघाट, खटीमा एवं द्वाराहाट महाविद्यालयों का स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के रूप में उच्चीकरण।
- उच्च शिक्षा पर योजनागत एवं गैर योजनागत वास्तविक व्यय 5563.18 लाख रु0 किया गया।
- उच्च शिक्षा में 14 महाविद्यालयों में परम्परागत विषयों के साथ-साथ इको-टूरिज्म फार्मेसी, नर्सरी टैक्नोलॉजी और आर्चड प्रबन्धन, फिश टैक्नोलॉजी, पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्ध इनटीरियर डैकोरेशन, मैडिकल लैब टैक्नोलॉजी, बायो टैक्नोलॉजी, पी0जी0डी0पी0, फारेस्ट्री एवं वाइल्ड लाइफ, प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं पोषण प्रबन्धन रोजगारपरक व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ।

2004–2005

- चक्राता एवं टनकपुर में नवीन महाविद्यालयों की स्थापना।
- शिक्षकों एवं प्राचार्यों के 70 तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 64 पदों का सृजन।
- उच्च शिक्षा में नामांकित विधार्थियों की संख्या 88857, जिसमें 42784 छात्र एवं 46073 छात्रायें सम्मिलित।
- 13 शासकीय एवं 07 अशासकीय महाविद्यालयों का राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) द्वारा मूल्यांकन।
- उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन हेतु “नैक” प्रायोजित एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित तथा शोध पत्रिका “एकेडमिका” का प्रथम अधिवेशन सम्पन्न।
- मानिला, कर्णप्रयाग, तलवाड़ी, नई टिहरी, चम्पावत, डाकपत्थर, हल्द्वानी (महिला) तथा देवप्रयाग महाविद्यालयों को यू0जी0सी0 की धारा 2(एफ) / 12(बी) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त। 27 महाविद्यालय यू0जी0सी0 की धारा 2(एफ) / 12(बी) मान्यता से आच्छादित।
- रानीखेत, उत्तरकाशी एवं हल्द्वानी महाविद्यालय आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु चयनित। इन महाविद्यालयों में उच्च स्तरीय प्रयोगशालाओं, शिक्षण कक्षों, जिमनेजियम एवं छात्रावास पुस्तकों एवं फर्नीचर तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु अनुदान स्वीकृत।
- उच्च शिक्षा पर योजनागत एवं गैर योजनागत वास्तविक व्यय रु0 5609.03 लाख।
- उच्च शिक्षा निदेशालय में कम्प्यूटर अनुप्रयोग :— 15 कम्प्यूटर, 01 सर्वर, 01 वी-सैट।

2005–2006.

- चौखुटा-दोषापानी (नैनीताल), एवं कपकोट (बागेश्वर) में दो नये महाविद्यालय स्थापित।
- शिक्षकों एवं प्राचार्यों के 33 तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 27 पदों का सृजन।
- उच्च शिक्षा में नामांकित विधार्थियों की संख्या 112012 जिसमें 52894 छात्रायें सम्मिलित।
- शासकीय महाविद्यालयों में 159 पदों पर लोक सेवा आयोग से चयनित प्राध्यापकों की तैनाती।
- प्रशिक्षण कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों के 61 शिक्षक ए0टी0आई0 नैनीताल में तथा 159 प्राध्यापकों ने आ0सी0एफ0ए0आई0 देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- 08 महाविद्यालयों के पुस्तकालय कर्मियों को लाईब्रेरी साप्टवेयर में प्रशिक्षण।
- उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ महाविद्यालयों में सिस्कों एकेडमी स्थापित एवं उत्तरकाशी में सी0सी0एन0ए0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ।
- लोहाघाट, रुद्रपुर एवं कोटद्वार महाविद्यालय आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु चयनित। इन महाविद्यालयों में उच्च स्तरीय प्रयोगशालाओं, शिक्षण कक्षों, जिमनेजियम एवं छात्रावास पुस्तकों एवं फर्नीचर तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु अनुदान स्वीकृत।
- उच्च शिक्षा में 10 महाविद्यालयों में परम्परागत विषयों के साथ-साथ इको-टूरिज्म फार्मसी, नर्सरी टैक्नोलॉजी, फिश टैक्नोलॉजी, पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्ध, इनटीरियर डैकोरेशन, मैडिकल लैब टैक्नोलॉजी, बायो टैक्नोलॉजी आदि रोजगारपरक व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ।
- शोध सोसायटी एकेडमिका का द्वितीय अधिवेशन ऋषिकेश महाविद्यालय में सम्पन्न।
- उच्च शिक्षा पर योजनागत एवं गैर योजनागत वास्तविक व्यय 6006.27 लाख रु0 किया गया।

2006–2007

- सोमेश्वर, गुरुड़ाबांज, भिक्यासैण, कॉडा, नैनीडांडा, त्यूनी, नरेन्द्रनगर, कोटाबाग, सतपुली व रुद्रप्रयाग में चालू सत्र में 10 महाविद्यालय स्थापित।
- शिक्षकों एवं प्राचार्यों के 147 तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 76 पदों का सुजन।
- बागेश्वर, नई टिहरी, अगस्त्यमुनि के शासकीय महाविद्यालयों तथा हरिद्वार के चिन्मय अशासकीय महाविद्यालय का आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु चयनित।
- निदेशालय में गठित गुणवत्ता सुनिश्चयीकरण प्रकोष्ठ द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिसमें 34 महाविद्यालयों के प्राचार्यों/समन्वयकों के द्वारा प्रतिभाग।
- बागेश्वर एवं गोपेश्वर महाविद्यालय, का “नैक” से प्रत्यायन सम्पन्न।
- 51 महाविद्यालयों को एजुकेशन सैटेलाईट के माध्यम से अध्यापन हेतु एडूसैट सिस्टम उपलब्ध।
- महाविद्यालयों के दो अधिकारियों को ई-गर्वनेन्स में प्रशिक्षण प्रदत्त।
- महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये जिला स्तर पर संविदा के आधार पर 147 शिक्षक चयन।
- शिखर परियोजना के अन्तर्गत 49 शासकीय एवं 14 अशासकीय महाविद्यालयों में O Level कम्प्यूटर प्रशिक्षण संचालित।
- उच्च शिक्षा पर योजनागत एवं गैर योजनागत प्राविधानित वास्तविक व्यय रु0 8429.79 लाख।
- राज्य गठन के समय 17 महाविद्यालयों के निजी भवन के सापेक्ष 35 महाविद्यालयों के भवन लगभग पूर्ण तथा 15 महाविद्यालयों के भवन निर्माणाधीन, जिनमें 13 भवन रहित महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण भी सम्मिलित है। आलोच्य वर्ष में 02 परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पन्न।
- लोक सूचना अधिकारियों/प्राचार्यों को सूचना अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित।
- 12 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को बायोटैक्नोलौजी हेतु राज्य बायोटैक्नोलौजी कार्यक्रम के अन्तर्गत पुस्तकों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता प्रस्तावित।
- ऋषिकेश, उत्तरकाशी, एम०बी० हल्द्वानी तथा पिथौरागढ़ महाविद्यालयों में टिश्यू कल्वर प्रयोगशाला की स्थापना।

2007–2008

- महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये जिला स्तर पर संविदा के आधार पर 147 विजिटिंग शिक्षक एवं 144 संविदा शिक्षक आमंत्रित।
- उच्च शिक्षा निदेशालय की 0.998 हेक्टेयर भूमि हस्तान्तरित तथा निदेशालय के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये का आगणन शासन को प्रेषित।
- शिक्षकों के चयन वेतनमान तथा रीडर पदनाम इत्यादि के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण।
- स्ववित्त पोषित अशासकीय उच्च शिक्षण संस्थानों की भौति 18 शासकीय महाविद्यालयों में भी 2700 सीटों पर स्ववित्त पोषित आधार पर बी०एड० पाठ्यक्रम संचालन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया।
- महाविद्यालयों के दो अधिकारियों द्वारा जैण्डर वजटिंग में प्रतिभाग तथा आलोच्य वर्ष में अनेक अधिकारियों को कम्प्यूटर संचालन इत्यादि क्षेत्रों में प्रशिक्षण।

- समस्त लोक सूचना अधिकारियों/प्राचार्यों द्वारा दो चरणों में सूचना का अधिकार अधिनियम पर उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल के तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण में प्रतिभाग।

2008–2009

- उच्च शिक्षा की जनसामान्य तक पहुँच को सुनिश्चित करने हेतु राजकीय महाविद्यालय, रिखणीखाल (पौढ़ी गढ़वाल) एवं राजकीय महाविद्यालय, थत्यूड (टिहरी गढ़वाल) की स्थापना की गई। प्रदेश में कुल राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 67 हो चुकी है।
- थत्यूड, रिखणीखाल, एवं नैनीडांडा के राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य (03), प्रवक्ता (31) एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी (46) के पदों की स्वीकृति हुई तथा डाकपत्थर में प्रवक्ता के (2) एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के (2) पदों की स्वीकृति हुई।
- प्रदेश के 15 शासकीय महाविद्यालयों में स्व-वित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ।
- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के 623 रिक्त पदों के प्रति वैकल्पिक व्यवस्थान्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु 453 विजिटिंग प्रवक्ता तथा संविदा शिक्षकों की व्यवस्था।
- निदेशालय का ढाँचा पुनर्गठित करते हुए 20 अतिरिक्त पदों का सूजन एवं समायोजन के उपरान्त कुल पदों की संख्या 45 के स्थान पर 65 हो गयी है।
- दूरस्थ शिक्षा परिषद नई दिल्ली की “कर्न्चर्जेंस” योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के 09 शासकीय तथा 02 अशासकीय महाविद्यालय सहयोगी संस्था के रूप में आच्छादित।
- 12 शासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों को राज्य बायोटैक्नोलोजी कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- शासकीय महाविद्यालय जैती यू0जी0सी0 की धारा 2 (एफ) एवं 12 (बी0) के अन्तर्गत सहायता सूची में सम्मिलित।
- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश को स्वायत्त महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में यू0जी0सी0 की स्वीकृति।
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 2007–08 में राष्ट्रीय सेवा योजना के एक स्वयं सेवी व एक जिला समन्वयक को देश का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त।
- है0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा।
- दून विश्वविद्यालय में भवन के कार्यों को गति प्रदान तथा प्रो0 गिरिजेश पंत द्वारा विश्वविद्यालय के नये कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण।
- दून एवं उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की परिनियमावली प्रख्यापित।

2009–2010

- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम चरण में स्नातकोत्तर प्राचार्यों के 15 रिक्त पदों तथा स्नातक प्राचार्य के 42 रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति के माध्यम से पूरित किया गया। द्वितीय चरण में 01 स्नातक प्राचार्य को संयुक्त निदेशक पद पर तथा 10 शिक्षकों को उप निदेशक / स्नातक प्राचार्य पद पर प्रोन्नत किया गया।
- लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न विषयों में चयनित 41 शिक्षकों को प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में नियुक्ति प्रदान की गई है।
- वर्ष 2008–09 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 15 राजकीय महाविद्यालयों में बी0एड0 कक्षाओं का संचालन।
- महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य के सुचारू संचालन हेतु 386 विजिटिंग / संविदा प्रवक्ताओं को शिक्षण सत्र 2009–10 में आमंत्रित किया गया।

- बालगंगा महाविद्यालय सेन्दुल केमर (ठिहरी गढवाल) को अनुदान सूची में सम्मिलित करते हुए इस महाविद्यालय में कुल 23 पदों का सृजन किया है।
- कम्प्यूटर प्रशिक्षण शिखर प्रोजेक्ट की व्यवस्था 2009–10 वर्ष में भी 44 महाविद्यालयों में पूर्ववत् संचालित रही।
- 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कार्मिकों को अनुमन्य कराया जा चुका है तथा शिक्षकों को यूजी0सी0 वेतनमान अनुमन्य कराये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किया जा चुका है।
- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षकों को न्यूनतम रु0 8000/- एवं अधिकतम रु0 10000/- मानदेय को बढ़ाकर विजिटिंग प्रवक्ताओं के समान रु0 15000/- मासिक मानदेय अनुमन्य कराया गया।
- चम्पावत के राजकीय महाविद्यालय में प्रवक्ताओं के 06 एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 09 पदों की स्वीकृति हुई, इसके अतिरिक्त राज0 महाविद्यालय गरुड़, नरेन्द्र नगर, काण्डा, भिकियासैण, गुप्तकाशी एवं गरुड़बाँज में प्राचार्य के (06), प्रवक्ताओं के (25) एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के (54) पदों की स्वीकृति हुई।
- थलीसैण के राजकीय महाविद्यालय हेतु 5.0 हेठो वन भूमि का हस्तान्तरण किया गया।
- विभिन्न महाविद्यालयों के भवन निर्माण इत्यादि की 30 योजनायें, निर्माण के विभिन्न चरणों में संचालित हैं।
- उच्च शिक्षा में ई–लर्निंग तकनीकी के प्रयोग हेतु विचार मन्थन।
- प्रदेश के समस्त शासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों एवं निजी स्ववित्त पोषित बी0एड0 व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन में मानकों का कड़ाई से अनुपालन करवाने एवं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु शासन द्वारा चार जांच दलों का गठन करके महाविद्यालयों एवं संस्थानों का प्रदेश व्यापी सघन निरीक्षण/अनुश्रवण कराया गया।

2010–2011

- वर्ष 2010–11 में निदेशक एवं सयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा) के रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से पूरित किये जाने के साथ साथ प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रशासनिक एवं शिक्षण कार्यों के कुशल संचालन हेतु 04 स्नातक प्राचार्यों को स्नातकोत्तर प्राचार्य के रिक्त पदों तथा 05 वरिष्ठ प्रवक्ताओं को स्नातक स्तर के प्राचार्य के रिक्त पदों के प्रति प्रोन्नति प्रदान की गयी।
- नव स्थापित राजकीय महाविद्यालय, माजरा महादेव तहसील थलीसैण(पौड़ी) को शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों की संख्या बढ़ कर 70 हो गयी है। इसी क्रम में स्नातक कला संकाय के अन्तर्गत 06 विषयों के साथ राजकीय महाविद्यालय, कनालीछीना (पिथौरागढ़) को अनुमति (विलयरैन्स) प्रदान की गई।
- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्व–वित्त पोषित बी0 एड0 पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के क्रम में राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट एवं उत्तर काशी को अनुमति प्राप्त होने से बी0 एड0 कालेजों की संख्या 15 से बढ़ कर 17 हो गयी है।
- वर्ष 2010 में स्व0 वित्त पोषित बी0 एड0 पाठ्यक्रम सुचारू रूप से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में निदेशालय स्तर से विभागाध्यक्ष/फैकल्टी के रिक्त पदों को पूरित किया गया।

- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न विषयों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों की आपूर्ति हेतु निदेशालय स्तर पर साक्षात्कार के माध्यम से 344 रिक्त पदों के सापेक्ष 252 संविदा प्रवक्ताओं का चयन कर उन्हें प्रदेश के सुदूरवर्ती पर्वतीय महाविद्यालयों में तैनाती दी गयी। प्रदेश शासन द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 05 प्रवक्ताओं को राजकीय महाविद्यालयों में सुचारू रूप से पठन—पाठन संचालित किये जाने हेतु पर्वतीय क्षेत्र के महाविद्यालयों में नियुक्ति प्रदान की गयी। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों को पूरित किये जाने हेतु NET अर्हताधारी अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण शासन द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा (SET) आयोजित करने हेतु शासनादेश निर्गत कर SET परीक्षा को सम्पन्न कराने का दायित्व कुमायूँ विश्वविद्यालय नैनीताल को दिया गया है।
- प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कार्यों के कुशल संचालन हेतु महाविद्यालयों की मांग के अनुरूप 01 प्राचार्य, 88 प्रवक्ता एवं 100 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों का सृजन किया गया।
- दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत एड्सेट के माध्यम से संचालित किये जाने हेतु शासन द्वारा उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र देहरादून के सहयोग से प्रदेश में 25 राजकीय महाविद्यालयों में एड्सेट कार्य क्रम के क्रियान्वयन किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है, जिसके प्रथम चरण में कुमायूँ मण्डल के 12 तथा गढ़वाल मण्डल के 13 महाविद्यालय लाभान्वित हुए।
- प्रदेश शासन द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से वर्ष 2010–11 से वर्ष 2013–14 तक स्वायत्तशासी सरकार के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- UGC की संस्था NAAC (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) बंगलोर द्वारा राजकीय महाविद्यालय मानिला (अल्मोड़ा) एवं राजकीय महिला महाविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल) का मूल्यांकन किया गया है।
- राजकीय महाविद्यालय कपकोट (बागेश्वर) राजकीय महाविद्यालय चौखुटिया (अल्मोड़ा) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया अन्तिम चरण में गतिमान है। दोनों महाविद्यालयों हेतु चयनित वन भूमि की N.P.V जमा है।
- प्रदेश शासन द्वारा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं में से 18 प्रवक्ताओं को वरिष्ठ वेतनमान एवं 99 प्रवक्ताओं को चयन वेतनमान स्वीकृत किया गया है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड प्रशासनिक एकादमी, नैनीताल द्वारा प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यों एवं वरिष्ठ प्राध्यापकों को 25–25 के 07 वैचों में 06 दिवसीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया।

- प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में नये प्रोन्नत 40 प्राचार्यों को उत्तराखण्ड प्रशासनिक एकादमी नैनीताल में वित्तीय एवं प्रबन्धकीय प्रशिक्षण 20–20 के 02 बैचों में दिया गया। इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के लेखा से सम्बन्धित लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को 30–30 के 02 बैचों में माह दिसम्बर 2010 एवं फरवरी 2011 में वित्तीय प्रशिक्षण दिये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।
- उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की सातवी वर्षगाँठ पर 12 अक्टूबर 2010 को उच्च शिक्षा निदेशालय को उसके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है।
- राजकीय महाविद्यालय डोईवाल (देहरादून), स्याल्दे एवं मानिला (अल्मोड़ा) में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में पठन–पाठन प्रारम्भ किया गया।
- एम0 बी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल) में स्व–वित्त पोषित आधार पर स्नातकोत्तर स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी पाठ्कम प्रारम्भ किया गया।
- शासकीय महाविद्यालयों में 07 स्नातकोत्तर एवं 16 स्नातक प्राचार्यों के पदों पर प्रोन्नति।

2011–2012

- शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 131 पदों का सृजन।
- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रशासनिक, शैक्षणिक, शोध, स्वरोजगारपरक शिक्षा, संसाधन में वृद्धि, नवीन विषयों को प्रारम्भ करने के आलोक में दिनांक 26 एवं 27 दिसम्बर, 2011 को दून विश्वविद्यालय, देहरादून में प्रदेश के प्राचार्यों की बैठक का आयोजन।
- 4 निजी विश्वविद्यालयों को एल0ओ0आई0 निर्गत।
- समूह “ग” सेवानियमावली का प्रख्यापन।
- प्रवक्ताओं के 272 पदों का अधियाचन।
- निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए नीति का प्रख्यापन।
- एकेडेमिका सम्मेलन 14 से 15 एवं 16 मार्च, 2012 को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर में आयोजित।
- एडुसैट से व्याख्यानों का प्रसारण प्रारम्भ।
- स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्राचार्यों की प्रोन्नति।

2012–2013

- राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता पद के चयन के लिए उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना।
- राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष।
- उच्च शिक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनाओं व शासनादेशों को संकलित कर “उच्च शिक्षा संदर्शिका” का प्रकाशन।
- राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा कराये जा रहे अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न।
- विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की अर्हता हेतु ‘सेट’ परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन।
- प्रदेश में पॉच निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु आशय पत्र का निर्गमन।
- सितारगंज में राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास।
- प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उद्यमिता प्रशिक्षण, गुणात्मक उच्च शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन इत्यादि विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन।
- राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 535 संविदा प्रवक्ताओं को आमंत्रण।
- राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम के लिए 30 प्रवक्ताओं व 6 विभागाध्यक्षों का चयन।
- तीन राजकीय महाविद्यालयों को यू0जी0सी0 की मान्यता प्राप्त होने पर प्रदेश में यू0जी0सी की मान्यता प्राप्त कुल राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 36।

प्रदेश में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति एवं नवीन प्रवृत्तियां महाविद्यालयों की स्थापना एवं विकास

सम्प्रति, प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कुल 24 विश्वविद्यालय परिसर तथा 389 महाविद्यालय व शिक्षण संस्थान उपलब्ध हैं। 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना में असेवित क्षेत्रों में तेजी के साथ महाविद्यालयों की स्थापना हुई है तथा राज्य में महाविद्यालयों में प्रवेशार्थी लक्ष्य समूह 17 – 24 आयु वर्ग की जनसंख्या (1268478) के आधार पर 11225 की जनसंख्या पर एक महाविद्यालय उपलब्ध है। इस आयु वर्ग में नामांकित विद्यार्थियों का अनुपात, जिसे सकल नामांकन अनुपात अथवा जी0ई0आर0 भी कहा जाता है, वर्तमान में 14.17 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। (जी0ई0आर0 प्रदेश में 17–24 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या (2001) –1268478 के प्रतिशत के रूप में प्रदेश में सामान्य उच्च शिक्षा में विविध परिसरों सहित नामांकित छात्र संख्या – 1,79,756 का अनुपात है) तालिका सं0 – 01 से स्पष्ट है कि हाल के वर्षों में राज्य में महाविद्यालयों के सन्तुलित क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता दी गयी है। फलस्वरूप राज्य में जनपदवार महाविद्यालयों का औसत लगभग 8.69 हो गया है। यह उल्लेखनीय है कि मैदानी भौगोलिक पृष्ठभूमि के जनपदों में अशासकीय महाविद्यालयों के अपेक्षाकृत अधिक संकेत्रण को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से अधिकांशतः असेवित क्षेत्रों में शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना को प्राथमिकता प्रदान की गयी है। तालिका संख्या–02 से स्पष्ट है कि कुल 70 शासकीय महाविद्यालयों में से 56 (80%) पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थित 11 जनपदों में स्थापित हैं जबकि 38 अशासकीय महाविद्यालयों में 33 (87%) मैदानी भौगोलिक पृष्ठभूमि के 03 जनपदों में स्थापित हैं। यही नहीं, उच्च शिक्षा के विविधीकरण एवं विशिष्टीकरण (Diversification & Specialisation) दोनों ही दिशाओं में प्रयास किये गये हैं। बालिकाओं को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहित करने हेतु पृथक महिला महाविद्यालय, हल्द्वानी में स्थापित है जबकि अन्य समस्त सह शिक्षा महाविद्यालयों में भी उन्हें शिक्षण शुल्क में शतप्रतिशत छूट प्रदान की गयी है।

उत्तराखण्ड में भौगोलिक दुरुहता एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की स्थानीय कठिनाईयों के सन्दर्भ में उच्च शिक्षा में पहुँच एवं समता हेतु भौगोलिक संकेतक अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी समझे गये हैं। इस दृष्टि से उत्तराखण्ड में सम्प्रति उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले महाविद्यालयों की संख्या प्रति हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 2.11 हो गयी है, जबकि राज्य गठन के समय यह संख्या मात्र 0.64 थी। स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा में पहुँच एवं समता (Access & Equity) को सुविधाजनक रूप में बढ़ाने का लक्ष्य राज्य में महत्वपूर्ण रूप में प्राप्त किया गया है।

तालिका संख्या – 01
उत्तराखण्ड में महाविद्यालयों का जनपदवार वितरण

नाम	शासकीय	अशासकीय			विविध	महायोग
		अनु०	अनानु०	योग		
कुमॉर्यू मण्डल						
नैनीताल	5	-	1	1	1	7
बागेश्वर	4	-	-			4
अल्मोड़ा	9	1	-	1	1	11
पिथौरागढ़	6	-	-			6
चम्पावत	3	-	-			3
उधमसिंह नगर	4	1	6	7		11
योग कुमाऊँ मण्डल	31	2	7	9	2	42
गढ़वाल मण्डल						
पौड़ी गढ़वाल	9	-	2	2	2	13
चमोली	7	-	-	-	-	7
रुद्रप्रयाग	4	-	-	-	-	4
उत्तरकाशी	4	-	-	-	-	4
टिहरी गढ़वाल	9	1	-	1	1	11
देहरादून	5	6	4	11	-	16
हरिद्वार	1	7	8	15	-	16
योग गढ़वाल मण्डल	39	14	15	29	3	71
योग उत्तराखण्ड	70	16	22	38	5	113

राजकीय महाविद्यालयों में भूमि व भवन की स्थिति

(अ) भूमि व भवन की प्राप्ति

- | | |
|---|----|
| (i) राजकीय महाविद्यालय जिनके पास भवन उपलब्ध हैं | 36 |
| (ii) राजकीय महाविद्यालय जिनके पास भूमि है परन्तु भवन नहीं हैं | 13 |
| (iii) राजकीय महाविद्यालय जिनके पास भूमि व भवन नहीं हैं | 13 |
| (iv) निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय | 06 |
| (v) भवन निर्मित लेकिन हस्तगत नहीं हुए हैं | 02 |

(ब) छात्र संख्या के आधार पर भवन विहीन महाविद्यालयों की स्थिति

छात्र संख्या	राठ महाविधि जिनके पास भूमि है लेकिन भवन नहीं है।	राठ महाविधि जिनके पास भूमि व भवन नहीं है।
100 से कम	3 (काण्डा, गुरुड़बांज, चकराता)	4 (मजरा महादेव, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, थत्युड़)
101 से 200	4 (दोषापानी, रिखणीखाल, त्यूनी, नैनबाग)	4 (कोटाबाग, कपकोट, गरुड़, नरेन्द्र नगर)
201 से 300	2 (सोमेश्वर, भिक्षिसासैंण)	1 (सतपुली)

301 से 400	—	1 (मुन्सियारी)
401 से 500	1 (बलुवाकोट)	1 (चिन्न्यालीसौण)
501 से 600	1 (चौखुटिया)	1 (गंगोलीहाट)
601 से 700	1 (टनकपुर)	—
701 से 800	1 (बड़कोट)	1 (लक्सर)
योग	13	13

छात्र संख्या के आधार पर राजकीय महाविद्यालयों की स्थिति

विद्यार्थियों की संख्या	महाविद्यालयों की संख्या	प्रति महाविद्यालय में विद्यार्थियों की औसत संख्या
0–100	8 (11%)	46
101–500	30 (43%)	215
501–1000	13 (19%)	683
1001–2000	5 (7%)	1382
2001 से अधिक	14 (20%)	5071
कुल योग	70 (100%)	1338

तालिका संख्या – 02
शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयों का भौगोलिक क्षेत्रवार वितरण*

क्षेत्र / महाविद्यालय	शासकीय	अनुदानित
पर्वतीय क्षेत्र		
स्नातक महाविद्यालय	46	2
स्नातकोत्तर महाविद्यालय	9	-
विधि महाविद्यालय	1	-
योग पर्वतीय क्षेत्र	56	2
मैदानी क्षेत्र		
स्नातक महाविद्यालय	7	6
स्नातकोत्तर महाविद्यालय	7	8
योग मैदानी क्षेत्र	14	14
सम्पूर्ण उत्तराखण्ड		
स्नातक महाविद्यालय	53	8
स्नातकोत्तर महाविद्यालय	16	8
विधि महाविद्यालय	1	-
महायोग	70	16

* विश्वविद्यालयों के परिसरों को छोड़कर।

सुदृढ़ीकरण एवं अवस्थापना विकास :

महाविद्यालयों के संख्यात्मक विकास के साथ-साथ उनके विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण को भी राज्य गठन के पश्चात उच्च प्राथमिकता दी गयी है जिसके अन्तर्गत प्रयोगशाला, उपकरणों, पुस्तकालयों का रखरखाव पुस्तकों एवं फर्नीचर आदि के क्य हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाना सम्मिलित है। शासकीय महाविद्यालयों के मात्रात्मक विस्तार से इनके सुदृढ़ीकरण एवं गुणवत्ता उन्नयन हेतु प्राप्त बजट पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हुआ है। अधिकांश शासकीय महाविद्यालयों में संकायों एवं विषयों की संख्या कम होने से सीमित विषयों में ही अध्ययन की सुविधा उपलब्ध हो पायी है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर कक्षायें केवल 16 महाविद्यालयों में संचालित हो रही हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के गुणवत्ता संरक्षण एवं संवर्द्धन के क्षेत्र में कार्यरत यू०जी०सी० एवं नैक जैसी संस्थायें महाविद्यालयों में निरन्तर पाठ्यक्रम एवं विषयों के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने पर जोर देती रही हैं। साथ ही नवस्थापित महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों, छात्रावासों तथा कीड़ा एवं अन्य शिक्षणेत्तर गतिविधियों के आयोजनार्थ अवस्थापना सुविधाओं की समुचित व्यवस्था भी अपरिहार्य है। इस दृष्टि से भी स्थापित महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण की योजना हेतु उच्चतर परिव्यय का औचित्य सिद्ध होता है। डाकपत्थर, स्याल्डे, मानिला, जयहरीखाल, नई टिहरी, कर्णप्रयाग, डाकपत्थर, नारायणनगर 08 महाविद्यालयों का स्नातकोत्तर स्तर पर उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन में गतिमान है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन :

उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप महाविद्यालयों में परम्परागत विषयों के साथ—साथ इकोटूरिज्म, फार्मसी, नर्सरी टैक्नोलॉजी एण्ड ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, इन्टीरियर एण्ड एक्सटीरियर डेकोरेशन, फिश टैक्नोलॉजी, जर्नलिज्म एण्ड मॉस कम्यूनिकेशन, पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन, एडवरटाइजिंग आदि में 06 माह की अवधि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम तथा एक वर्षीय डिप्लोमा के रोजगारपरक/व्यावसायिक रोजगार परक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। साथ ही 10 शासकीय महाविद्यालयों – रुद्रपुर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, कोटद्वार, काशीपुर, गोपेश्वर, रानीखेत, रामनगर, हल्द्वानी तथा ऋषिकेश में वानिकी एवं वन्य जन्तु प्रबन्धन, पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन, एडवरटाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एण्ड सेल्स मैनेजमेंट, फिशरीज, फौरेस्टरी एवं वाइल्ड लाईफ मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल टैक्नीक्स एवं स्पेसिमैन प्रिप्रेशन, मृदा संरक्षण एवं जलागम प्रबन्धन, बायोटैक्नोलॉजी, औद्योगिक रसायन, ऑफिस मैनेजमेंट एण्ड सेकेट्रियल प्रैक्टिस, फौरेन ट्रेड प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम यू०जी०सी० के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 10 शासकीय महाविद्यालयों में एवं 02 अशासकीय महाविद्यालयों में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से अनेक स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में 16 राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित हैं।

पारंपरिक तथा खुली एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के एकीकरण की कनवर्जेंस योजना ।

उच्च शिक्षा को समाज के वंचित वर्गों तक पहुंचाने तथा साथ ही इसकी गुणवत्ता के संवर्द्धन के उददेश्य से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की शीर्षस्थ नियामक संस्था दूरस्थ शिक्षा परिषद (डिस्टेन्स एजूकेशन काउन्सिल) नई दिल्ली के निर्देशन में प्रारम्भ की गई इस योजना में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इंग्नू) तथा पारंपरिक शिक्षण संस्थानों की परस्पर सहभागिता से इंग्नू के गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रमों को जन-जन तक सुलभ कराया जा रहा है। इस योजना से इंग्नू के द्वारा उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण पाठ्यसामग्री, उच्च शिक्षण में सैटेलाइट एवं ऑन लाइन एजूकेशन जैसी नवीनतम तकनीकी के प्रयोग तथा पारंपरिक उच्च शिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षक—विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियात्मक विधि इत्यादि को एक साथ लाया जा सकेगा, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तीन महत्वपूर्ण उददेश्यों— पहुँच, (Access) समता (Equity) तथा गुणवत्ता (Quality) की प्राप्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

इस योजना के प्रारंभिक वर्ष में दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा संबंधित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को रु०— 4 लाख का अनावर्तक अनुदान तथा पहले तीन वर्ष तक रु०—3 लाख का आवर्तक अनुदान उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है। सहभागी संस्थान को विभिन्न उपलब्ध माडलों के अन्तर्गत कार्यक्रम शुल्क का एक निश्चित भाग अपनी आय के रूप में कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्रयोग में लाये जाने की भी व्यवस्था है।

इस योजना में यू०जी०सी० की धारा 2 (एफ) अथवा धारा (3) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त समस्त विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त पेशेवर संस्थानों तथा स्थापित शैक्षणिक ट्रैक रिकार्ड वाले संबद्ध महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों को सम्मिलित किया जा रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर सम्मिलित किए गये 185 संस्थानों में से उत्तराखण्ड राज्य के आच्छादित संस्थानों का विवरण अंग्रेजित तालिका में प्रदर्शित है।

तालिका संख्या – 03

दूरस्थ शिक्षा परिषद् नई दिल्ली की 'कन्वर्जेंस' (Convergence) योजना के अन्तर्गत आच्छादित उत्तराखण्ड के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय—

क्रम सं०	महाविद्यालय का नाम	शासकीय/अशासकीय	प्रारम्भ का वर्ष
1	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़	शासकीय	2009
2	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट (चम्पावत)	शासकीय	2009
3	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर	शासकीय	2009
4	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर (नैनीताल)	शासकीय	2009
5	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर (उधमसिंह नगर)	शासकीय	2009
6	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी	शासकीय	2009
7	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर (चमोली)	शासकीय	2009
8	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरिखाल (पौड़ी)	शासकीय	2009
9	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर	शासकीय	2009
10	डी०ए०बी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय देहरादून	अशासकीय	2008
11	एम०के०पी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय देहरादून	अशासकीय	2008
12	राजकीय महिला महाविद्यालय हल्द्वानी	शासकीय	2009

आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना :

प्रत्येक जनपद में एक महाविद्यालय को आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित किये जाने की योजना के अन्तर्गत अब तक 13 महाविद्यालय आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित किये गये हैं। आदर्श महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को समयानुकूल बनाने तथा महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयोगशाला एवं शिक्षण कक्षों का निर्माण, जिम्नेजियम एवं छात्रावास व्यवस्था, आधुनिकतम प्रयोगशाला उपकरणों, पुस्तकों एवं फर्नीचर का क्य तथा एक-एक डिग्री स्तरीय रोजगारपरक पाठ्यक्रम-औद्यानिकी, बायोटेक्नॉलोजी, मेडिकल लैब टेक्नॉलोजी, बी०बी०ए० इत्यादि प्रारम्भ किये गये हैं।

तालिका संख्या –04

राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अद्यतन स्वीकृत/रिक्त पदों की स्थिति (जनवरी, 2013 तक)

	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
प्राचार्य स्नातक/स्नातकोत्तर	70	56	14
शिक्षक	1366	511	855
शिक्षणेत्तर कर्मचारी	1404	668	736

नोट—शिक्षकों के रिक्त पदों पर अल्पकालिक वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत 535 संविदा शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है।

उच्च शिक्षा में सूचना एवं कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी का समावेश—

- शिखर परियोजना के अन्तर्गत 500 से अधिक छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों में शिक्षा प्रदाताओं द्वारा एवं 500 से कम छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों में शासन द्वारा कम्प्यूटर प्रयोगशालायें स्थापित की गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत 33 शासकीय एवं 04 अशासकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशालायें स्थापित की गयी। वर्तमान में 14 शासकीय एवं 14 अशासकीय महाविद्यालयों में शिखर परियोजना संचालित हो रही हैं।
- राजकीय महाविद्यालय उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में सिस्को एकेडमी स्थापित की गयी है, तथा उत्तरकाशी में सी0सी0एन0ए0 पाठ्यक्रम संचालित हो गया है।

शोध एवं विकास :

राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों में प्रोत्साहित करने, शोध कार्यों के प्रकाशन और शोध में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से एकेडेमिका (उच्च शिक्षा उन्नयन एवं शोध विकास समिति) की स्थापना की गयी है जिसका द्वितीय अधिवेशन 2005–06 में ऋषिकेश में आयोजित हुआ जिसमें प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापकों द्वारा शोध पत्र प्रस्तुत किये गये। इससे पूर्व एकेडेमिका का अधिवेशन “Transition to knowledge society: opportunities and challenges” विषय पर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ में मार्च 15 एवं 16 2009 को आयोजित किया गया। एकेडेमिका का तृतीय अधिवेशन 14, 15, एवं 16 मार्च, 2012 को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में आयोजित किया गया, जिसके लिए USAC व UGC द्वारा अनुदान स्वीकृत है। 16 महाविद्यालयों में वर्ष 2009–10 में कला विज्ञान व वाणिज्य संकायों में क्रमशः 132, 54, व 23 विद्यार्थी (100 पुरुष एवं 109 महिलाएं) पी–एचडी0 के लिए पंजीकृत थे। वर्ष 2010–11 में पंजीकृत शोधार्थियों की संख्या 215 हो गयी। शासकीय महाविद्यालयों में स्थापना से 2009–10 तक कुल 462 विद्यार्थियों ने पी–एचडी0 उपाधि प्राप्त की है। वर्ष 2007–08 में शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिकाओं में 220 शोध पत्रों के प्रकाशन के साथ–साथ कार्यशालाओं व गोष्ठियों में 290 शोध पत्रों का प्रस्तुतीकरण भी किया गया। संप्रति प्रदेश के 16 शासकीय महाविद्यालयों में 61 शोध परियोजनाएं भी संचालित हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008–09 में 03 तथा 2010–11 में 02 नैक कार्यशालाएं आयोजित हुई।

विभिन्न महाविद्यालयों में आयोजित राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय सेमिनारों का विवरण

क्र० संख्या	सेमिनार का नाम	आयोजन तिथि	राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय-विभाग	आयोजक महाविद्यालय
1	Gender and development in India	12-13 Mar 2011	(National Political Science)	D.A.V. PG College Dehradun
2	Environmental Management & Bio-diversity-	26-27 Feb 2011	National AESA & MANU Society	PG College Rishikesh
3	State of Uttarakhand : Development & Governance	07-08 Mar, 2011	National (Political Science)	PG College Ranikhet
4	Protection & Enforcement of IPR in a knowledge Economy : Opportunities and challenges	05-06 Mar, 2011	National (Commerce)	PG College Pithoragarh
5	Role of Science & Technology in Development of Uttarakhand State	24-25 Sept 2010	State (Physics)	PG College Bageshwar
6	Dalit literature-Past trends and Present concerns	04-05 Oct 2010	National (English)	Degree College Jaiharikhali
7	Strategic Significance of the Himalayan Region in the context of Indian Security	07-09 June 2010	National (Military) Science	PG College Pithoragarh
8	Land and Environmental Degradation in the Hills of Uttarakhand	05-07 June 2010	National (Geology)	PG College Pithoragarh

गुणवत्ता सुनिश्चयीकरण एवं संवर्धन :

राज्य गठन के पश्चात् गुणवत्ता सुनिश्चयीकरण हेतु महाविद्यालयों को नैक के द्वारा मूल्यांकन एवं प्रत्यायन कराने का कार्य भी तीव्र गति से आरम्भ हुआ है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक महाविद्यालय जो यू०जी०सी० की धारा-२(एफ)एवं १२ बी द्वारा प्रमाणित है, में नैक स्टीयरिंग कमेटी की स्थापना की गयी है तथा मूल्यांकित महाविद्यालयों में आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयीकरण प्रकोष्ठ (IQAC) की स्थापना हुई है। अब तक १९ शासकीय एवं ०९ अशासकीय महाविद्यालयों का राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा मूल्यांकन किया जा चुका है। १० शासकीय तथा ०५ अशासकीय महाविद्यालयों का मूल्यांकन नैक से कराया जाना प्रस्तावित है। महाविद्यालयों में इसके लिए आवश्यक चेतना उत्पन्न करने के उद्देश्य से अब तक निदेशालय स्तर पर स्थापित राज्य गुणवत्ता सुनिश्चयीकरण प्रकोष्ठ द्वारा ०७ कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है।

तालिका संख्या-05

उत्तराखण्ड के शासकीय/अनुदानित महाविद्यालयों में मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की प्रगति

विवरण	शासकीय	अनुदानित	योग
महाविद्यालयों की कुल संख्या	70	16	86
यू०जी०सी० 2 (एफ) एवं 12 (बी०) से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय	36	14	50
नैक से प्रत्यायनित महाविद्यालय	19	10	29
यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय जिनके प्रत्यायन की प्रक्रिया गतिमान है	10	04	14

वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक राज्य स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ द्वारा निम्नांकित सेमीनार/वर्कशापों एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया :

- 16 जुलाई 2008 को निदेशालय में महाविद्यालय के प्राचार्यों की एक जागरूकता बैठक का आयोजन जिसमें 32 महाविद्यालयों द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद बंगलौर के प्रभारी निदेशक प्रो० रविचन्द्रन रैड्डी तथा उप-सलाहकार बी०एस० मधुकर द्वारा स्वयं प्रतिभागियों को मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की नवीन विधि की जानकारी प्रदान की गयी।
- 17–18 अक्टूबर, 2008 को निदेशालय में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके प्रथम दिवस में प्रदेश के गैर –प्रत्यायनित महाविद्यालयों तथा दूसरे दिन प्रत्यायनित महाविद्यालयों के प्राचार्यों /नैक प्रभारियों के द्वारा अपने—अपने महाविद्यालयों में प्रत्यायन /पुनः प्रत्यायन के सम्बन्ध में हुई प्रगति तथा विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। कार्यशाला का उद्घाटन पूर्व निदेशक प्रो० पी०सी० बाराकोटी द्वारा किया गया। इस अवसर पर राज्य गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ द्वारा प्रकाशित वार्षिक न्यूज़ लैटर “क्वालिटी” का विमोचन भी किया गया।
- 30 दिसम्बर, 2008 को निदेशालय तथा बी०एस०एम० अशासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रूड़की हरिद्वार के संयुक्त तत्वावधान में रूड़की में गढ़वाल मंडल के महाविद्यालयों की एक दिवसीय संगोष्ठी /कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो० राणा, उपनिदेशक प्रो० एस०सी० साह, सहायक निदेशक डा० एल०डी० पलरिया तथा नैक प्रभारी डा० सी०डी० सूंठा ने भी प्रतिभागिता की। इस संगोष्ठी में आयोजक महाविद्यालय की स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण भी किया गया तथा मूल्यांकन की नवीन विधि पर प्रस्तुतीकरण प्रदर्शित किये गये।
- राज्य गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ के तत्वावधान में अब तक मार्च, 2009 तथा सितम्बर, 2009 में न्यूज़ लैटर के 02 अंकों का प्रकाशन किया जा चुका है। वर्ष 2010–11 में एक आई०क्यू०ए०सी० सेमीनार का आयोजन बी०एस०एम० पी०जी० कालेज रूड़की में किया गया।

प्रशासन एवं प्रबन्धः

प्रदेश के महाविद्यालयों के विकास एवं उन पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से प्रदेश में उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना वर्ष 2001 में की गयी थी। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से सम्बन्धित वित्तीय कार्यों के सम्पादन हेतु एवं उन पर प्रभावी नियन्त्रण रखने तथा उच्च शिक्षा निदेशालय का शासन से समन्वय रखने के उद्देश्य से देहरादून में निदेशक, उच्च शिक्षा के शिविर कार्यालय की स्थापना की गयी है, जिसका संचालन सम्प्रति उपनिदेशक द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय के दायित्व एवं कर्तव्य परिशिष्ट संख्या – 01 में प्रदर्शित हैं। सम्प्रति निदेशालय में नवीन स्वीकृत ढाँचे के पश्चात् अब 65 स्वीकृत पद हो गये हैं।

शासकीय महाविद्यालयों में सृजित पदों की वार्षिक प्रवृत्तियां :

राज्य गठन के पश्चात महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि तथा स्थापित महाविद्यालयों में नये संकायों एवं विषयों के खोले जाने से पदों के सृजन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तालिका सं0–06 से स्पष्ट है कि 2001–2006 की अवधि में कुल पदों में 668 पदों की वृद्धि हुई जिसमें सर्वाधिक वृद्धि 2003–04 में तथा इसके पश्चात 2006–07 में हुई है।

तालिका संख्या – 06

उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों / कर्मचारियों के विगत वर्षों में पदों की संख्या (2001–2013)

वर्ष	राजपत्रित	अराजपत्रित	योग	पूर्व वर्ष के सापेक्ष % वृद्धि
2001–2002	918	795	1713	—
2002–2003	926	808	1734	1.23
2003–2004	1032	932	1964	13.26
2004–2005	1102	996	2098	6.82
2005–2006	1135	1023	2158	2.85
2006–2007	1282	1099	2381	10.33
2007–2008	1282	1099	2381	—
2008–09	1321	1164	2485	1.01
2009–10	1358	1227	2585	4.02
2010–2011	1447	1327	2774	4.89
2011–2012	1452	1453	2905	4.72
2012–2013 जनवरी 2013	1452	1453	2905	—

उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड का प्रशासनिक ढांचा

	निदेशक (01)	
	संयुक्त निदेशक (01)	
वित्त नियंत्रक(01)	उप निदेशक (02)	उप निदेशक(शिविर)(01)
लेखाधिकारी(01)	सहायक निदेशक (03)	सहायक निदेशक (01)
लेखाकार (01)	वैयक्तिक सहायक (01)	प्रवर सहायक(01)
सहायक लेखाकार(01)	वरिं प्रशासनिक अधिकारी (01)	आशुलिपिक(01)
लेखापरीक्षक(02)	प्रशासनिक अधिकारी (06)	कनिष्ठ सहायक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर(02)
	मुख्य सहायक (06)	वाहन चालक(01)
	अन्वेषक कम संगणक /डाटा ऑपरेटर (02)	परिचारक(02)
	प्रवर सहायक (08)	
	स्टैनो/सहायक कम्प्यूटर परिचालक(03)	
	कनिष्ठ सहायक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर(03)	
	वाहन चालक (03)	
	परिचारक (10)	

तालिका संख्या – 07

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों का विवरण

स्वीकृत पद	2008–09 जनवरी, 2009	2009–10 जनवरी, 2010	2010–11 जनवरी, 2011	2011–12 जनवरी, 2012	2012–13 जनवरी, 2013
पुस्तकालयाध्यक्ष	25	25	25	25	25
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	—	—	—	04	04
प्रशासनिक अधिकारी	—	—	—	39	39
मुख्य सहायक	—	—	—	40	40
प्रवर सहायक	28	30	32	67	67
कार्यालय अधीक्षक	25	25	25	—	—
कनिष्ठ सहायक	147	152	169	106	106
सहायक लेखाकार	06	06	06	06	06
प्रयोगशाला सहायक	199	214	256	273	273
आर्टिस्ट	02	02	02	02	02
तबलाबादक	09	09	09	09	09
सहा० पुस्तकालयाध्यक्ष	09	12	19	33	33
कैटलागर	02	02	02	02	02
आशुलिपिक	22	22	22	22	22
तकनीशियन	02	02	02	02	02
इलेक्ट्रीशियन / मैकेनिक	15	17	18	18	18
टैक्नीशियन फोटोग्राफी	—	—	01	01	01
कम्प्यूटर आपरेटर	—	—	01	01	01
टूर एंड ट्रेनिंग असिस्टेंट	—	—	01	01	01
दफतरी	24	24	24	—	—
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	549	577	656	753	753
कुल योग	1064	1119	1270	1404	1404

कार्मिक प्रशिक्षण :

- कार्मिक प्रशिक्षण उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्राचार्यों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2008–09 में प्रशिक्षण कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों से एक प्राचार्य तथा एक प्राध्यापक के द्वारा राष्ट्रीय योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में लोक नीति निर्माण एवं प्रक्रिया पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी में भी 05 प्राध्यापकों ने बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर आयोजित कार्यशाला में तथा एक प्राध्यापक ने ई–गर्बनेंस में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। 48 महाविद्यालयों के लेखाकारों / तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को विभाग द्वारा लेखा एवं वित्तीय प्रबन्ध में प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2007–08 में 141 प्रवक्ताओं ने यू०जी०सी० अभिविन्यास एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया। वर्ष 2009–10 में 01 अधिकारी को

उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में मैंटरिंग स्किल्स प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। वर्ष 2010–11 में उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में डी०ओ०पी०टी० के सौजन्य से 25–25 के सात बैचों में प्राचार्यों एवं वरिष्ठ प्रवक्ताओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण, 20–20 के दो बैचों में नव प्रोन्नत प्राचार्यों को वित्तीय एवं प्रबन्धकीय प्रशिक्षण, 05–05 के 03 बैचों में लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं 30–30 के 02 बैचों में महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को वित्तीय प्रशिक्षण दिया दिया गया। वर्ष 2010–11 में प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में नये प्रोन्नत 40 प्राचार्यों को उत्तराखण्ड प्रशासनिक एकादमी नैनीताल में वित्तीय एवं प्रबन्धकीय प्रशिक्षण 20–20 के 02 बैचों में दिया गया। इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के लेखा से सम्बन्धित लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को भी 30–30 के 02 बैचों में माह दिसम्बर 2010 एवं फरवरी 2011 में वित्तीय प्रशिक्षण दिया गया।

उच्च शिक्षा में नामांकन प्रवृत्तियां:

विगत वर्षों में प्रदेश में सामान्य उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का कुल नामांकन तेजी से बढ़ा है। वि०वि० परिसरों सहित वर्ष 2005–06 में कुल नामांकन 122127 था जो 2007–08 एवं 2008–09 में बढ़कर क्रमशः 137837 एवं 152471 तथा वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में कुल नामांकन बढ़कर क्रमशः 167409 एवं 1,79,756 हो गया है। उच्च शिक्षा पर कुल व्यय में भी 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना में सतत वृद्धि हुई है। वर्ष 2011–12 में कुल नामांकन 1,83,716 हो गया है।

तालिका संख्या – 08

उच्च शिक्षा निदेशालय के नियंत्रणाधीन राजकीय व अनुदानित महाविद्यालयों में 10 वीं, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल वास्तविक व्यय एवं प्रति विद्यार्थी औसत व्यय की प्रवृत्तियां।

वर्ष	उच्च शिक्षा पर वास्तविक कुल व्यय लाख रु० में	अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या (वि०वि० परिसरों व निजी शिक्षण संस्थानों को छोड़कर)	प्रति विद्यार्थी औसत व्यय (रुपयों में)	प्रतिशत परिवर्तन (पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष)
2002-03	4117.64	82426	4996	-
2003-04	5563.18	84581	6582	(+) 31.74
2004-05	5609.03	88857	6312	(-) 4.10
2005-06	6006.27	98326	6109	(-) 5.93
2006-07	7428.71	106038	7006	(+) 14.68
2007-08	7050.40	117724	5989	(-) 14.52
2008-09	7453.27	129496	5757	(+) 5.71
2009-10	10776.99	132359	8142	(+) 41.42
2010-11	15887.86	147908	10742	(+) 31.93
2011-12	12075.06	1,58,142	10487	(-) 2.37
2012-13 (प्राविधानित)	17124.92	1,52,637	11219	(+)7.27

उच्च शिक्षा पर योजनागत एवं गैर योजनागत वास्तविक व्ययः—

राज्य गठन के पश्चात् उच्च शिक्षा पर योजनागत एवं गैर योजनागत कुल व्यय में लगातार वृद्धि हुई है किन्तु वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2010–11 में पूर्व वर्ष के सापेक्ष कमशः 41.42 प्रतिशत तथा 31.93 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि उल्लेखनीय है जिसे तालिका संख्या—09 में प्रदर्शित किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पहले 02 वर्षों में कुल व्यय कमशः 7050.4 लाख रु0 तथा 7433.27 लाख रु0 रहा है, जो पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 5.71 प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2010–11 में औसत व्यय में 47.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2012–13 में रु0 17124.92 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया। वर्ष 2013–14 हेतु रु0 19742.04 का आय–व्ययक प्रस्तावित किया गया है।

तालिका संख्या— 09

उच्च शिक्षा पर योजनागत एवं गैर योजनागत वास्तविक व्यय 2001–02 से 2012–13

वर्ष	वास्तविक व्यय (लाख रु0 में)	पूर्व वर्ष के सापेक्ष : वृद्धि
2001–02	3490.13	—
2002-03	4117.64	17.98
2003-04	5563.18	35.11
2004-05	5609.03	0.83
2005-06	6006.27	7.08
2006-07	7396.21	40.34
2007-08	7050.4	(-) 5.10
2008-09	7453.27	5.71
2009-10	10188.31	44.59
2010-11	15887.86	47.42
2011-12	12075.06	(-) 23.99
2012-13 (प्राविधान)	17124.92	—
2013-14 (प्रस्तावित)	19742.04	—

भावी कार्यक्रम एवं व्यूह नीतियः

- समस्त अर्ह महाविद्यालयों का नैक द्वारा मूल्यांकन एवं प्रत्यायन कराना।
- मूल्यांकित एवं प्रत्यायनित महाविद्यालयों में आन्तरिक गुणवत्ता विनिश्चयन प्रकोष्ठ (IQAC) की स्थापना तथा उन्हें प्रभावशाली बनाना
- समस्त अवशेष महाविद्यालयों को यूजी0सी0 की धारा–2एफ एवं 12 बी0 मान्यता प्राप्त कराने हेतु मानकों को पूर्ण कराना यथा— भूमि क्षय/भवन निर्माण, पदों का सृजन एवं नियुक्तियों अतिरिक्त विषयों एवं संकायों की स्वीकृति इत्यादि, जिससे इन महाविद्यालयों को भी मूल्यांकन हेतु अर्ह बनाया जा सके।
- शोध एवं प्रसार को प्रोत्साहन प्रदान करना।

- शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- पाठ्यक्रम सामग्री का विकास एवं डिजिटाईजेशन (Content development & Digitisation) करना।
- समस्त महाविद्यालयों में इन्टरनेट-कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करना।
- प्राध्यापकों की लोक सेवा आयोग से नियुक्ति प्रक्रिया को तीव्र करने के प्रयास करना।
- अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु रैमेडियल पाठ्यक्रम संचालित करना।
- दूरस्थ महाविद्यालयों में आवासीय भवनों तथा छात्रावासों का निर्माण कराना।
- उत्तराखण्ड की भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुरूप रोजगार परक पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहन देना, उद्योग जगत के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित करना तथा देश एवं प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थाओं के साथ परस्पर सहयोग स्थापित करना।
- शासकीय महाविद्यालयों में निजी क्षेत्र से कम शुल्क पर स्ववित्त पोषित बी०ए० पाठ्यक्रमों का विस्तार करना।
- शासकीय महाविद्यालयों में निजी क्षेत्र में कम शुल्क पर स्ववित्त पोषित अन्य रोजगारपरक जैसे एम०बी०ए०, एम०सी०ए०, वायोटेक्नालॉजी, माइक्रोवाइलॉजी, मेडिकल प्रयोगशाला तकनीकी, पत्रकारिता, पाठ्यक्रमों को संचालित करना।
- निदेशालय स्तर से महाविद्यालयों का औचक निरीक्षण कर प्रशासन व प्रबन्ध को प्रभावशाली बनाना।
- सुदृढ़ एवं सम्भावनायुक्त महाविद्यालयों को स्वायत्तशासी महाविद्यालयों के रूप में विकसित करना।
- पारंपरिक एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के समन्वय के द्वारा शिक्षा की पहुँच एवं गुणवत्ता में अभिवृद्धि करना।
- महाविद्यालयों एवं निदेशालय में प्रशासन तथा अभिलेख प्रबन्धन में सूचना तकनीक का नवाचार पर आधारित उपयोग करना।
- महाविद्यालयों के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर अनुश्रवण एवं निरीक्षण की प्रणाली को प्रदेशस्तर पर प्रभावशाली बनाना।
- भगवान पुर (हरिद्वार), सितारगंज (ऊधम सिंह नगर), बगवाली पोखर (अल्मोड़ा) एवं मांसी में नये राजकीय महाविद्यालयों को खोले जाने की प्रक्रिया शासन स्तर पर गतिमान।
- राजकीय महाविद्यालय जैती, गरुड़ाबॉज, गैरसैण, कर्णप्रयाग, डाकपत्थर में नये संकाय/विषय प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर गतिमान।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में उच्च शिक्षा हेतु प्रस्तावित योजनाओं का विवरणः

1. 17 राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु भवन निर्माण।
 2. राजकीय महाविद्यालय काण्डा, भिक्यासैण, मानिला, चम्पावत, थत्यूड, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, बागेश्वर, डाकपत्थर आदि में कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत विभिन्न नवीन विषयों का आरम्भ किया जाना।
 3. उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, राजकीय महाविद्यालय, लक्सर, भिक्यासैण, नागनाथ पोखरी, चौखुटा-दोषापानी, थलीसैण व कपकोट में भवन निर्माण।
 4. प्रदेश के 30 राजकीय महाविद्यालयों में चालू लघु एवं वृहद निर्माणकार्यों को पूर्ण किया जाना।
 5. प्रदेश के उन 13 महाविद्यालयों जिनके पास वर्तमान में भूमि नहीं है, के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया को प्राथमिकता के क्रम में गतिमान करना।
 6. प्रदेश के 13 ऐसे महाविद्यालय जिनके पास भूमि है किन्तु अपना भवन नहीं है, के लिए भवन निर्माण प्रक्रिया को गतिमान करना।
 7. 08 स्नातक महाविद्यालयों का उच्चीकरण कर स्नातकोत्तर स्तर पर लाना।
-
8. केन्द्र पुरोनिधानित एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत शासकीय महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं हेतु तैयार करने की प्रशिक्षण योजना।

वर्तमान में प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र में दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई विस्तृत एवं प्रभावी व्यवस्था नहीं है। प्रस्तावित योजना प्रदेश के 13 जनपदों में अवस्थित आदर्श महाविद्यालयों में संचालित की जानी प्रस्तावित है। इस योजना के प्रथम चरण में वर्ष 2010–11 में 04 महाविद्यालयों – गोपेश्वर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर को चयनित किया गया है, जिसमें राजस्व पक्ष में रु0 50.00 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2013–14 में राजस्व पक्ष में रु0 50.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है। इस योजना से लक्षित वर्ग— अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों एवं महिलाओं को स्थानीय स्तर पर मार्ग दर्शन सुविधा उपलब्ध होने से उनके कौशल एवं प्रतियोगितात्मक क्षमता तथा रोजगार अवसरों में वृद्धि होना सम्भावित है।

उच्च शिक्षा विभाग
वर्ष 2013–2014 हेतु प्रस्तावित आय–व्ययक

(धनराशि रु० हजार में)

पुनरीक्षित अनुमान		मुख्य / लघु शीर्षक लेखाशीर्षक	आय–व्ययक	
वर्ष 2012–2013	आयोजनागत्		वर्ष 2013–2014	आयोजनागत्
1	2	3	4	5
		2202—सामान्य शिक्षा		
		03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा		
-	36720	001—निदेशन एवं प्रशासन	-	40630
02	-	102—विश्वविद्यालयों को सहायता (राष्ट्रीय विधिविधि)	02	-
98002	361001	102—विश्वविद्यालयों को सहायता	176745	390488
266982	805928	103—राजकीय कालेज एवं संस्थान	300567	875353
11501	380150	104—अराजकीय कालेज तथा संस्थाओं को सहायता	14001	420150
500	01	107—छात्रवृत्तियाँ	500	01
500	600	800—अन्य व्यय	200	600
-	-	05—भाषा विकास	-	-
-	549	102—भारतीय भाषा का विकास	-	300
600	-	मतदेय 796—जनजाति क्षेत्र उपयोजना	900	-
-	-	भारित	-	-
5000	-	103—राजकीय कालेज एवं संस्थान (अनुजाति योजना)	5000	
383085	1584949	योग	497915	1727522
		पूँजी लेखा		
200001	-	4202—विश्वविद्यालयों की पूँजीगत परिस्मितियों का सृजन	335000	-
203500	-	4202—शिक्षा, खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत व्यय	310000	-
-	6000	7610—सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज	-	6000
403501		योग	645000	6000
786586	1590949	महायोग	1142915	1733522

परिशिष्ट – 01

उच्च शिक्षा निदेशालय के दायित्व एंव कर्तव्य

- प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्रबन्धन, नियन्त्रण विकास तथा मूल्यांकन का दायित्व ।
- प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शासकीय व्यवस्था के माध्यम से वेतन वितरण एंव उनसे संबंधित अन्य प्रशासनिक कार्य तथा समय–समय पर पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण ।
- अध्यापकों की वर्तमान रिक्तियों तथा आने वाले शिक्षा वर्ष के दौरान संबंधित रिक्तियों की सूचना महाविद्यालयों से प्राप्त करना तथा सूचित रिक्तियों की विषयवार समेकित सूची आयोग को विज्ञापन एंव चयन हेतु प्रेषित करना ।
- भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति ।
- सेवा निवृत्ति पर भविष्य निधि में जमा अंतिम देय धनराशि की स्वीकृति ।
- उच्च शिक्षा से संबंधित न्यायालयीय वाद संबंधी कार्य ।
- शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों के अभिलेखों का मुख्यालय की आडिट इकाई द्वारा आन्तरिक सम्प्रेक्षण ।
- विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय रखते हुए उच्च शिक्षा के नियमों, परिनियमों एंव अधिनियमों तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के दायित्व का निर्वहन ।

परिशिष्ट – 02

उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सम्पादित होने वाले प्रमुख कार्यों का विवरण

(क) अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित कार्य

- शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अनुदान का आवंटन किया जाना ।
- शैक्षिक एंव शिक्षणेत्तर नये पदों के सृजन संबंधी कार्यवाही, रिक्त होने वाले पदों का सततीकरण तथा पदों का स्थायीकरण ।
- शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन निर्धारण, चयन वेतनमान स्वीकृत किया जाना तथा वेतन संबंधी विवाद ।

- सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति तथा सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि की राशि का अन्तिम भुगतान।
- नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा पूर्व में चल रहे महाविद्यालयों में नये विषयों को खोले जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करना।
- महाविद्यालयों का आडिट कराना तथा आडिट आपत्तियों का निराकरण, अनियमितताओं की जाँच कराना, विभिन्न स्त्रोतों से शासन को प्राप्त शिकायतों की जाँच कराना तथा तदनुसार कार्यवाही करना।
- महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक/प्रशासक नियुक्त किये जाने से संबंधित कार्यवाही।
- महाविद्यालयों के अध्यापकों की वर्तमान रिक्तियों और आने वाले शैक्षणिक वर्ष के दौरान सम्भावित रिक्तियों की सूचना महाविद्यालयों से प्राप्त करना।
- प्रकीर्ण संस्थाओं को सहायक अनुदान प्रदान किया जाना।
- शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियों को अनुमोदन प्रदान किया जाना।

(ख) राजकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित कार्य

- राजकीय महाविद्यालयों का वार्षिक बजट तैयार कराना, शिक्षकों की तैनाती/स्थानान्तरण तथा प्रोन्नति के मामले।
- इन महाविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं प्राचार्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच एवं अनुशासनिक/प्रशासनिक कार्यवाही करना।
- नये पदों का सृजन तथा नये राजकीय महाविद्यालयों के खोले जाने हेतु शासन को संस्तुति करना।
- शिक्षकों/कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार के अवकाश की स्वीकृति।
- प्राचार्य/शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पेंशन, भविष्य निधि तथा विभिन्न प्रकार के अग्रिम के निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही करना।
- महाविद्यालयों के विकास हेतु अनावर्तक/आवर्तक धनराशि का आवंटन।
- प्रशासनिक निरीक्षण।

(ग) प्रदेश के अशासकीय तथा राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षित होने की दशा में शिक्षकों, कार्यालय अधीक्षकों, तथा पुस्तकालयाध्यक्षों/सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन निर्धारण का कार्य उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

(घ) अशासकीय/शासकीय महाविद्यालयों से संबंधित न्यायालयों में चल रहे वादों की पैरवी छात्रों की विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों की स्वीकृति, ऋण छात्रवृत्ति की वसूली तथा उच्च शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार के ऑकड़े एकत्रित करना और विकास हेतु योजना बनाना तथा शिक्षकों/प्राचार्यों का प्रशिक्षण कार्य भी निदेशालय द्वारा किया जाता है, साथ ही साथ विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से संबंधित समस्याओं के संबंध में शासन को परामर्श देना एवं इनसे संबंधित विधान मण्डल में उठाये गये प्रश्नों इत्यादि के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना।

(ङ) उच्च शिक्षा का वार्षिक बजट तैयार करना।

(क) निदेशक के अधिकार

- अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सीमा रु0 1.00 लाख।
- असाधारण अवकाश स्वीकृति की सीमा 6 माह।
- कैरियर एडवान्समेन्ट योजना (Career Advancement Scheme) के अन्तर्गत वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान संस्तुत करने का अधिकार।
- निष्प्रयोज्य सामग्री के अपलेखन (Write-off) के अन्तर्गत प्रत्येक मद में रु0 20000/- की सीमा तक, किन्तु एक वर्ष में कुल रु0 50,000/- की अधिकतम सीमा तक।
- महाविद्यालयों में छात्रकोष की बचत राशि एवं ब्याज की धनराशि को विगत 03 वर्षों तक की राशि को संस्था के विकास में प्रयोग किये जाने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) द्वारा प्राचार्यों की आहूत बैठक के कार्यवृत (Minutes) में व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

(ख) संयुक्त निदेशक के कार्य/दायित्व

- उच्च शिक्षा निदेशालय तथा अधीनस्थ कार्यालय/महाविद्यालयों के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण यथा— नियुक्तियों, स्थानान्तरण, वेतन निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, कार्यालय अधीक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों की गोपनीय चरित्र प्रविष्टियों का अंकन/रख—रखाव।
- शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त तथा अनानुदानित महाविद्यालयों की स्थायी/अस्थाई सम्बद्धता के प्रकरण, नये विषयों/संकायों का खोला जाना, नये महाविद्यालयों की स्थापना, नई योजनाओं का क्रियान्वयन तथा बजट प्रस्ताव।
- शासकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेन्शन/उपादान/भविष्य निधि अन्तिम भुगतान/सामूहिक बीमा उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के समर्त प्रकरण।
- अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति, पदों के सृजन के प्रस्ताव तथा तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के अनुमोदन के प्रकरण।
- महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा तथा भवन निर्माण कार्य के नये प्रस्तावों पर कार्यवाही।
- महाविद्यालयों के स्टाफ स्टेटमेन्ट सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन, रोस्टर पंजिकाओं का रख—रखाव, विभागीय प्रगति विवरण/दिग्दर्शिका का प्रकाशन।
- शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के सम्परीक्षा के प्रकरण/अनुपालन आव्याओं की समीक्षा/निस्तारण।
- निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा समय—समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों का निस्तारण।

परिशिष्ट – 03

**उपनिदेशक (उच्च शिक्षा) शिविर कार्यालय देहरादून के कार्यों एवं
दायित्वों का विवरण**

(क) प्रशासनिक कार्य

- अशासकीय महाविद्यालयों की प्रशासनिक जॉच एवं निरीक्षण संबंधी कार्य।
- महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की संस्तुति।
- विधान सभा के प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराना।
- नये विषय खोलने के लिये, पैनल में शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के प्रतिनिधि के रूप में महाविद्यालयों का निरीक्षण करना।
- शासन तथा उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा दिये गये विशेष कार्यों का सम्पादन।
- अपने क्षेत्र के अशासकीय महाविद्यालयों में शैक्षिक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की अनुज्ञा प्रदान करना।
- शासन के आदेश पर राजकीय महाविद्यालयों के खोले जाने हेतु क्लीयरेंस देने के लिये निरीक्षण करना एवं संस्तुति देना।
- अशासकीय महाविद्यालयों को दिये गये अनुदान की उपभोग अवधि में एक वर्ष की सीमा तक वृद्धि करना।
- पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक एवं कोऑर्डिनेटर के पदों को छोड़कर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करना।
- अपने क्षेत्र के सभी अशासकीय महाविद्यालयों/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से नियत तिथि पर स्टाफ स्टेटमेंट प्राप्त करना।
- क्षेत्र के महाविद्यालय/स्नातकोत्तर महाविद्यालय से सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों के पेंशन कागजात तैयार करने के कार्य पर निगरानी रखना। सेवानिवृत्ति के छः मास पूर्व समर्त पत्रादि निदेशक को उपलब्ध कराना।
- अशासकीय महाविद्यालयों में नियुक्त प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण कराया गया या नहीं पर शासन को आख्या भेजना।

(ख) विकास/सांख्यिकी संबंधी कार्य

- विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से सांख्यिकी ऑकड़े एकत्रित करना, विश्लेषण करना तथा उन्हें संकलित करके निदेशालय को प्रेषित करना।
- क्षेत्र में उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण करना।
- महाविद्यालयों में शैक्षिक कार्य संबंधी प्रवृत्तियों की सूचना एकत्र करना तथा संकलित करना।
- उपरोक्त के संबंध में समय—समय पर प्रकाशन निकालना।
- राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य की समीक्षा।

(ग) वित्तीय कार्य:

- महाविद्यालयों द्वारा 80/75 प्रतिशत शुल्काय जमा किये जाने की जॉच करना और उन महाविद्यालयों का बकाया वसूल करना, जिन्होंने उचित अंश जमा न किया हो। समय—समय पर प्रगति की सूचना निदेशालय को देना।
- ऋण छात्रवृत्ति की वसूली की समीक्षा करना तथा वसूली करने हेतु विधिक एवं न्यायिक कार्यवाही करना।

- उ0प्र0 शैक्षिक संस्थाओं (आस्तियों) के अपव्यय निवारण अधिनियम 1974 के अन्तर्गत महाविद्यालयों के आस्तियों का लेखा रखना तत्संबंधी जॉच करना।
- उच्च शिक्षा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई सम्परीक्षा आख्या सहित निदेशालय को प्रेषित करना।
- आपदा स्थिति जैसे: बाढ़, सूखा, भूकम्प आदि के संबंध में क्षति का आंकलन करना व क्षतिपूर्ति अनुदान हेतु निदेशालय को संस्तुति करना।
- विभिन्न अनुदानों अनावर्तक अनुदानों से संबंधित महाविद्यालयों के आवेदन पत्र परीक्षण कर निदेशालय को उपलब्ध कराना।
- उपभोग प्रमाण—पत्र को महाविद्यालयों से प्राप्त करना तथा उनका सत्यापन कर निदेशालय को प्रेषित करना।
- नई पेशन योजनान्तर्गत सामान्य भविष्य निधि की कटौती तथा संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करना तथा उनके रख—रखाव को सुनिश्चित करना।
- महाविद्यालयों का लेखा परीक्षण करना।
- पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक के पदों को छोड़कर शेष सभी तृतीय एंव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन निर्धारण तथा भविष्य निधि से अग्रिम स्वीकृत करना।

परिशिष्ट – 04

छात्रवृत्तियों का विवरण

(रु0 प्रति हजार में)

छात्रवृत्ति का नाम	व्यय	व्यय	व्यय	प्राविधान	प्रस्ता वित		अभ्युक्ति
	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	
शोध छात्रवृत्ति	150	147	150	150	150	150	यह छात्रवृत्ति शोध छात्रों को अनुसंधान एवं शोध की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आधारभूत आवश्यकताओं, प्रयोगशाला उपकरण एवं शोध जर्नल्स/ सन्दर्भ ग्रन्थ हेतु स्वीकृत की जाती है।
विशेष छात्र—वृत्ति योजना	580	—	—	—	500	500	यह छात्र—वृत्ति चिकित्सा/ इंजिनियरिंग तथा अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत योग्य श्रेष्ठ तथा प्रतिभावान विद्यार्थियों को आर्थिक आधार पर प्रदान की जाती है। नियमों के अभाव में प्राविधानित की गई धनराशि व्यय नहीं हो पा रही है।

परिशिष्ट – 05
उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित राजकीय महाविद्यालयों की सूची

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम	स्नातक / स्नातकोत्तर	स्थापना वर्ष	UGC धारा 2(f)/12B के अन्तर्गत मान्यता	छात्र संख्या वर्ष 2011–12
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	
जनपद नैनीताल					
1.	एम० बी० राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वानी।	स्नातकोत्तर	1960 प्रा० 1982	मान्यता	13123
2.	रा० महिला महावि०, हल्द्वानी।	स्नातक	1995	मान्यता	937
3.	रा० स्नात० महाविद्यालय, रामनगर।	स्नातकोत्तर	1975	मान्यता	4615
4.	रा० महावि० दोषापानी, चौखुटा।	स्नातक	2005		169
5.	रा० महावि० कोटाबाग।	स्नातक	2006		137
जनपद बागेश्वर					
6.	रा० स्नात० महाविद्यालय, बागेश्वर।	स्नातकोत्तर	1974	मान्यता	2761
7.	रा० महाविद्यालय, कपकोट।	स्नातक	2005		195
8.	रा० महाविद्यालय, कॉडा।	स्नातक	2006		63
9	रा० महाविद्यालय, गरुड़	स्नातक	2006		108
जनपद अल्मोड़ा					
10	रा० स्नात० महावि०, रानीखेत।	स्नातकोत्तर	1973	मान्यता	2136
11.	रा० स्नात० महावि०, द्वाराहाट।	स्नातक	1983	मान्यता	735
12.	रा० महावि०, मानिला।	स्नातक	1989	मान्यता	626
13.	रा० महावि०, जैती।	स्नातक	1995	मान्यता	211
14.	रा० महावि०, चौखुटिया।	स्नातक	2001		569
15.	रा० महावि०, गुरुड़ाबांज।	स्नातक	2006		60
16.	रा० महावि०, सोमेश्वर।	स्नातक	2006		237
17.	रा० महावि०, भिक्यासैण।	स्नातक	2006		256
18.	रा० महावि०, स्याल्दे।	स्नातक	1979	मान्यता	637
जनपद पिथौरागढ़					
19.	रा० स्नात० महावि० पिथौरागढ़।	स्नातकोत्तर	1963	मान्यता	6959
20.	रा० स्नात० महावि०, बेरीनाग।	स्नातकोत्तर	1975	मान्यता	1543
21.	रा० महावि०, नारायणनगर।	स्नातक	1983	मान्यता	636
22.	रा० महावि०, बलूवाकोट, धारचूला।	स्नातक	1997		462
23.	रा० महावि०, मुन्द्यारी।	स्नातक	2001		359
24.	रा० महावि०, गंगोलीहाट।	स्नातक	2001		539
जनपद चम्पावत					
25.	रा० महावि०, चम्पावत।	स्नातक	1997	मान्यता	552
26.	रा० स्नात० महावि०, लोहाघाट।	स्नातकोत्तर	1979	मान्यता	1545

27.	रा० महावि०, टनकपुर।	स्नातक	2004		697
जनपद उधमसिंह नगर					
28.	रा० स्नात० महावि०, खटीमा।	स्नातकोत्तर	1988	मान्यता	6653

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम	स्नातक / स्नातकोत्तर	स्थापना वर्ष	UGC धारा 2(f)/12B के अन्तर्गत मान्यता	छात्र संख्या वर्ष 2011–12
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	
29.	रा० स्नात० महावि०, रुद्रपुर।	स्नातकोत्तर	1974	मान्यता	6920
30.	रा० स्नात० महावि०, काशीपुर।	स्नातकोत्तर	1979	मान्यता	7365
31	रा० महावि०, बाजपुर।	स्नातक	1995		838
जनपद पौड़ी गढ़वाल					
32.	रा० स्नात० महावि०, कोटद्वार।	स्नातकोत्तर	1971	मान्यता	5546
33.	रा० महावि०, बेदीखाल।	स्नातक	1979	मान्यता	170
34.	रा० महावि०, जयहरीखाल।	स्नातकोत्तर	1972	मान्यता	531
35.	रा० महावि०, चौबटाखाल।	स्नातक	1979	मान्यता	181
36.	रा० महावि०, थलीसैण।	स्नातक	2001		179
37.	रा० महावि०, नैनीडांडा।	स्नातक	2006		136
38.	रा० महावि०, सतपुली।	स्नातक	2006		280
39	रा० महावि०, रिखणीखाल।	स्नातक	2009		129
40	रा० महाविद्यालय, मजरा महादेव	स्नातक	2010		50
जनपद चमोली					
41	रा० स्नात० महावि०, गोपेश्वर।	स्नातकोत्तर	1966	मान्यता	2888
42.	रा० महावि०, जोशीमठ।	स्नातक	1995		200
43.	रा० महावि०, तलवाड़ी।	स्नातक	1997	मान्यता	363
44.	रा० महावि०, गैरसैण।	स्नातक	2001	मान्यता	247
45.	रा० महावि०, नागनाथ पोखरी।	स्नातक	2001		163
46.	रा० विधि० महावि०, गोपेश्वर।	स्नातक	2003		8
47	रा० महावि० कर्णप्रयाग	स्नातक	1979	मान्यता	1311
जनपद रुद्रप्रयाग					
48	रा० स्नात० महावि०, अगस्त्यमुनि।	स्नातकोत्तर	1974	मान्यता	3171
49	रा० महावि०, जखोली।	स्नातक	2001		208
50	रा० महावि०, रुद्रप्रयाग	स्नातक	2006		51
51	रा० महावि० गुप्तकाशी	स्नातक	2006		12
जनपद उत्तरकाशी					
52.	रा० स्नात० महावि०, उत्तरकाशी।	स्नातकोत्तर	1969	मान्यता	3317
53	रा० महावि०, बड़कोट।	स्नातक	1993		769
54	रा० महावि०, पुरौला।	स्नातक	1993		216
55	रा० महावि०, चिन्यालीसौँड।	स्नातक	2001		446

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम	स्नातक / स्नातकोत्तर	स्थापना वर्ष	UGC धारा 2(f)/12B के अन्तर्गत मान्यता	छात्र संख्या वर्ष 2011–12
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	
जनपद टिहरी					
56	रा० महावि०, नई टिहरी।	स्नातक	1979	मान्यता	1170
57	रा० महावि०, देवप्रयाग।	स्नातक	1984	मान्यता	161
58.	रा० महावि०, अगरोड़ा।	स्नातक	2001		215
59	रा० महावि०, चन्द्रबद्नी।	स्नातक	2001	मान्यता	255
60	रा० महावि०, नैनबाग।	स्नातक	2001		199
61	रा० महावि०, लम्बगाँव।	स्नातक	2001	मान्यता	173
62	रा० महावि०, पौखाल	स्नातक	2002	मान्यता	103
63.	रा० महावि०, नरेन्द्रनगर	स्नातक	2006		133
64	रा० महावि०, थत्यूड	स्नातक	2009		53
जनपद देहरादून					
65.	रा० महावि०, डाकपत्थर।	स्नातक	1993	मान्यता	2296
66.	रा० स्नात० महावि०, ऋषिकेश।	स्नातकोत्तर	1972	मान्यता	3765
67.	रा० महावि०, डोईवाला।	स्नातक	2001	मान्यता	1369
68	रा० महावि०, चकराता।	स्नातक	2004		76
69	रा० महावि०, त्यूनी।	स्नातक	2006		190
जनपद हरिद्वार					
70	रा० महावि०, लक्सर।	स्नातक	2001	मान्यता	841

परिशिष्ट – 06

उत्तराखण्ड राज्य में नैक से प्रत्यायनित महाविद्यालयों की सूची

क्र०	महाविद्यालय का नाम	नैक द्वारा प्रदत्त ग्रेड
1	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋशिकेष (देहरादून)	A
2	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर (उधमसिंहनगर)	C++
3	एम०बी०राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी (नैनीताल)	B+
4	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर (नैनीताल)	B+
5	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार (पौड़ी)	C++
6	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग (पिथौरागढ़)	B+
7	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत (अल्मोड़ा)	B
8	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर (उधमसिंहनगर)	B
9	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी	B++

10	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर (चमोली)	B++
11	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ (पिथौरागढ़)	B++
12	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर	C+
13	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा (उधमसिंह नगर)	C+
14	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट (चम्पावत)	C++
15	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, द्वाराहाट(अल्मोड़ा)	B
16	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयहरीखाल	C++
17	राजकीय महाविद्यालय, स्याल्दे(अल्मोड़ा)	C
18	राजकीय महाविद्यालय, मानिला (अल्मोड़ा)	B
19	राजकीय महिला महाविद्यालय, हल्द्वानी(नैनीताल)	B
20	डी०बी०एस० पी०जी० कालेज, देहरादून	B+
21.	दया नन्द महिला प्रशिक्षण कालेज, देहरादून	B+
.22	एम०के०पी० पी०जी० कालेज, देहरादून	B+
23.	चिन्मय महाविद्यालय, हरिद्वार	B
24.	कन्हैयालाल डी०ए०बी० पी०जी० कालेज, रुड़की	B
25	एस०एम०जे०एन० डिग्री कालेज, हरिद्वार	B
26	डी०ए०बी० पी०जी० कालेज, देहरादून	B+
27	बी०एस०एम० पी०जी० कालेज रुड़की।	B
28	श्री गुरु राम राय कालेज, देहरादून	B
29	आर०एम० पी०जी० कालेज हरिद्वार	C

परिशिष्ट – 07

उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों की सूची

(क) अनुदानित महाविद्यालय:

क्र० सं०	जनपद	महाविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	UGC धारा 2(f)/12B के अन्तर्गत मान्यता	छात्र संख्या 2011–12
1.	अल्मोड़ा	आर्य कन्या महाविद्यालय, अल्मोड़ा।	1974	मान्यता	46
2.	उधमसिंहनगर	चन्द्रावती तिवारी कन्या महावि. काशीपुर।	1986		772
3.	देहरादून	डी० डब्लू० टी० कालेज, देहरादून	1961	मान्यता	68
4.	देहरादून	डी० ए० बी० कालेज देहरादून।	1986	मान्यता	33558
5.	देहरादून	डी० बी० एस० कालेज, देहरादून।	1961	मान्यता	2921

6.	देहरादून	एम० के० पी० पी०जी० कालेज देहरादून।	1958	मान्यता	2451
7.	देहरादून	श्री गुरुराम राय कालेज देहरादून।	1960	मान्यता	3043
8.	देहरादून	एम० पी० जी० कालेज, मसूरी (देहरादून)	1963	मान्यता	1118
9.	हरिद्वार	आर०एम०पी० पी०जी० कालेज नारसन, रुड़की (हरिद्वार)	1950	मान्यता	688
10.	हरिद्वार	बी० एस० एम० पी०जी० कालेज, रुड़की (हरिद्वार)	1958	मान्यता	1326
11.	हरिद्वार	के० एल० डी० ए० वी० कालेज, रुड़की (हरिद्वार)	1960	मान्यता	1205
12.	हरिद्वार	चिन्मय डिग्री कालेज हरिद्वार।	1989	मान्यता	987
13.	हरिद्वार	एस०डी०पी०सी० कालेज रुड़की (हरिद्वार)	1966	मान्यता	1297
14.	हरिद्वार	एस०एम०जे०एन० कालेज, हरिद्वार।	1960	मान्यता	1430
15.	हरिद्वार	महिला महावि. सतीकुण्ड, कनखल, हरिद्वार।	1965	मान्यता	1327
16.	नई टिहरी	बाल गंगा सैन्दुल कैमर महावि० टिहरी	1991		681

परिशिष्ट – ०८
**शासकीय महाविद्यालयों में बी०एड० पाठ्यक्रम की वर्तमान एवं
निर्धारित सीटों का विवरण**

क्र० सं०	राजकीय महाविद्यालय का नाम	सृजित पद	राज्य सहायतित	स्वित्त पोषित
			बी०एड० पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीटों की संख्या	बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित / स्वीकृत सीटों की संख्या
1.	एम०बी० रा० स्ना० महा०, हल्द्वानी	07	70	स्वीकृत 100
2	रा० स्ना० महा०, पिथौरागढ़	07	70	प्रस्तावित 100
3	रा० स्ना० महा०, गोपेश्वर	07	70	स्वीकृत 100
4	रा० स्ना० महा०, कोटद्वार	06	60	स्वीकृत 100
5.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ऋषिकेश (देहरादून)।			प्रस्तावित 100
6.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,			स्वीकृत 100

	उत्तरकाशी ।			
7.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर ।			स्वीकृत 100
8.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुद्रपुर (उधमसिंह नगर) ।			स्वीकृत 100
9.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत (अल्मोड़ा) ।			स्वीकृत 100
10.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेरीनाग (पिथौरागढ़) ।			स्वीकृत 100
11.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग) ।			स्वीकृत 100
12.	राजकीय महाविद्यालय, बेदीखाल (पौड़ी गढ़वाल)			स्वीकृत 100
13.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खटीमा (उधमसिंह नगर) ।			स्वीकृत 100
14.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर (उधमसिंह नगर) ।			स्वीकृत 100
15.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर (नैनीताल) ।			स्वीकृत 100
16.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयहरीखाल (पौड़ी गढ़वाल) ।			स्वीकृत 100

स्ववित्त पोषित

क्र0 सं0	राजकीय महाविद्यालय का नाम	सृजित पद	बी0एड0 पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीटों की संख्या	बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित सीटों की संख्या
17.	राजकीय महाविद्यालय, डाकपत्थर (देहरादून) ।			स्वीकृत 100
18.	राजकीय महाविद्यालय, नैनीडांडा (पौड़ी गढ़वाल) ।			स्वीकृत 100
19.	राजकीय महाविद्यालय, गैरसेण (चमोली) ।			प्रस्तावित 100
20.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट (चम्पावत) ।			स्वीकृत 100
21.	राजकीय महाविद्यालय, चन्द्रबदनी (ठिहरी गढ़वाल) ।			प्रस्तावित 100
22.	राजकीय महाविद्यालय, लक्सर (हरिद्वार) ।			प्रस्तावित 100

23	राजकीय महाविद्यालय, भिकियासैण			प्रस्तावित 100
24	राजकीय महाविद्यालय, लम्बगाँव (प्रतापनगर)			प्रस्तावित 100

परिशिष्ट – 09

राजकीय महाविद्यालयों द्वारा अर्जित उपलब्धियाँ/विशिष्ट योगदान

महाविद्यालय का नाम	उपलब्धियाँ
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)	<ul style="list-style-type: none"> रोवर सुनील कुमार का राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु चयन तथा एन०सी०सी० के अन्तर्गत उदय भानु शुक्ला द्वारा गणतन्त्र परेड में राज्य का प्रतिनिधित्व
राजकीय महाविद्यालय, बाजपुर (ऊधमसिंह नगर)	<ul style="list-style-type: none"> एन०सी०सी० के अन्तर्गत विभिन्न कैम्पों में आयोजित प्रतियोगिताओं में 08 मेडल प्राप्त ।
राजकीय महाविद्यालय, कपकोट(बागेश्वर)	<ul style="list-style-type: none"> एन०सी०सी० के अन्तर्गत किये गये रक्त दान के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं पुरस्कृत ।
राजकीय महाविद्यालय, बड़कोट(उत्तरकाशी)	<ul style="list-style-type: none"> रोवर्स रैंजर्स के अन्तर्गत 2010 में 01 रोबर को राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त एवं 02 अन्य रोवर 2011 में राष्ट्रपति सम्मान हेतु चयनित ।
राजकीय महाविद्यालय, जयहरिखाल (लैंसडाउन)	<ul style="list-style-type: none"> रोवर्स रैंजर्स के अन्तर्गत श्री गोविन्द लिंगवाल , एम०ए० प्रथम को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त । राजकीय महाविद्यालय जयहरिखाल– “Role of Mathematics and its application in development of Science and Technology. (प्रस्तावित 21–22 मार्च, 2013)
राजकीय महाविद्यालय, कोटाबाग (नैनीताल)	<ul style="list-style-type: none"> एन०ए०ए०ए० के अन्तर्गत किये गये रक्त दान के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं पुरस्कृत ।
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर	<ul style="list-style-type: none"> विभिन्न विषयों में 15 शोध छात्रों का पंजीकरण सत्र 2010–11 में रसायन विज्ञान के एक छात्र द्वारा यू०जी०सी० जे०आर०एफ० तथा एक छात्र द्वारा नैट परीक्षा उत्तीर्ण राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय सम्मेलन का आयोजन प्रतियोगिता परीक्षाओं में विद्यार्थियों का चयन – बैंकिंग (1), समीक्षा अधिकारी (2), माध्यमिक प्रवक्ता लिखित परीक्षा (9), पी०सी०ए०स० प्रारम्भिक (6) वि०वि० परीक्षा 2010–11 में स्नातक कक्षाओं में 87 विद्यार्थियों एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में 18 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की । 20 खिलाड़ियों का कुमायूँ वि०वि० की विभिन्न टीमों में चयन । खो-खो महिला /पुरुष, किकेट महिला /पुरुष,, शतरंज तथा लॉन टेनिस में

	<p>अन्तर्राष्ट्रीय सेवा योजना रक्तदान शिविर में उप विजेता।</p> <ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय सेवा योजना रक्तदान शिविर में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदेश में पुरस्कृत। एन0सी0सी0 “B” एवं “C” परीक्षा में कमशः 44 एवं 38 कैडेट्स उर्तीण। फरवर, 2013 में मात्र सूचना आयुक्त द्वारा सूचना अधिकार विषय पर संगोष्ठी का आयोजन।
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़	<ul style="list-style-type: none"> सत्र 2011–12 में वाणिज्य के एक छात्र द्वारा यूजी0सी0 जे0आर0एफ0 तथा 2010–11 में एक छात्र द्वारा नैट परीक्षा उत्तीर्ण। कुमाऊँ विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोह 2011 में महाविद्यालय के विद्यार्थियों को एम0एस0सी0 बॉटनी में स्वर्ण पदक तथा बी0ए0 एवं बी0कॉम0 में रजत पदक। तीन राष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन। 14 विद्यार्थी विभिन्न विषयों में शोध छात्रों के रूप में पंजीकृत। राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत। रोवर्स/रेजर्स के अन्तर्गत कु0 ईवा बोरा, नीमा पाण्डे एवं गोविन्द बल्लभ पाण्डे को राष्ट्रपति पुरुस्कार प्राप्त। महाविद्यालय की वेबसाइट्स का प्रारम्भ होना। महाविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति प्रतियोगिता परीक्षा अध्ययन केन्द्र का गठन। बी0ए0 तृतीय वर्ष की छात्रा विनीता चौबे द्वारा विवि परीक्षा में 74 % अंक प्राप्त कर महाविद्यालय में प्रथम स्थान। अन्तर्राष्ट्रीय खेल–कूद प्रतियोगिताओं में छात्र वर्ग में विजेता तथा छात्र वर्ग में उप विजेता। विधायक निधि से महाविद्यालय में एक लाख रु0 की लागत से फर्नीचर क्रय। महाविद्यालय, पिथौरागढ़ में भू-गर्भ विज्ञान द्वारा आयोजित “Geology, Bio-diversity and natural resources of Himalayas and their intellectual property”- 14/15 Oct, 2012. महाविद्यालय में “Innovation in ethnopharmacology, Recent Developments in biological and chemical Sciences for social benefit. (प्रस्तावित 21–22 मार्च, 2013)
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत	<ul style="list-style-type: none"> एन0सी0सी0 छात्र/छात्रा इकाई की 04 कैडेट्स का पी0आर0डी0सी0 कैप, 01 छात्र का वैसिक माउण्टेनियरिंग कैप हेतु चयन तथा 01 छात्रा द्वारा पैरा ग्लाइडिंग कोर्स का संचालन। विधायक निधि से महाविद्यालय में क्रीडांगन का समतलीकरण तथा एक शिक्षण कक्ष के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत में “Higher Education: issues and challenges: Present Scenario” विषय पर नवम्बर, 2012 में संगोष्ठी आयोजित।
राजकीय स्नातकोत्तर	<ul style="list-style-type: none"> महाविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति प्रतियोगिता परीक्षा अध्ययन केन्द्र

महाविद्यालय, बागेश्वर	<p>का गठन।</p> <ul style="list-style-type: none"> स्नातकोत्तर स्तर में भौतिकी एवं संस्कृत प्रारम्भ। इग्नू एवं उत्तरांचल मुक्त विवि केन्द्रों पर नये पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ होना। वनस्पति विज्ञान प्रवक्ता डा० पालीबाल द्वारा दस शोध पत्र एक पत्र प्रकाशित। अन्तर्महाविद्यालय बॉली—बॉल प्रतियोगिता का आयोजन।
राजकीय महाविद्यालय, द्वाराहाट	<ul style="list-style-type: none"> एन०एस०एस० के 02 विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना शिविर चेन्नई में प्रतिभाग। महाविद्यालय का परीक्षाफल शतप्रतिशत। वाणिज्य संकाय की कक्षाओं का प्रारम्भ किया जाना। डा० चिन्मय जोशी प्रवक्ता, प्राणी विज्ञान को आई०बी०आर०आई० द्वारा आयोजित किसान मेला एवं पशु प्रदर्शनी में न्यायविद मनोनीत किया गया। महाविद्यालय इण्टरनैट एवं एडुसैट से जुड़ा। एन०सी०सी० कार्यक्रम के अन्तर्गत कोहिमा नागालैंड में आयोजित राष्ट्रीय शिविर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया।
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी	<ul style="list-style-type: none"> रोवर्स रैंजर्स कार्यक्रम के अन्तर्गत 03 छात्र-छात्राओं-इन्ड्रमणी चमोली, राजेन्द्र सिंह एवं कु० गंगा डोगरा को राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु चयनित किया गया तथा इनके द्वारा रोवर्स-रैंजर्स कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय समारोह में अहमदाबाद में प्रतिभाग किया गया। रवि कुमार तथा हिमांशु सुन्दरियाल उत्तर क्षेत्रीय अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में क्रमशः हॉकी एवं क्रिकेट में तथा कु० राजेन्द्री राणा एवं कु० अंजलि कोटियाल उत्तर पूर्वी अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में : महिला बॉलीबाल में चयनित। सुशील कुमारी डिमरी, दीपक सिंह चौहान एवं कु० रजनी राणा रोवर्स रैंजर्स में राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु चयनित। डा० हर्षवन्ती बिष्ट (अर्थशास्त्र विभाग) ने 04 तथा डा० जी०के० डिंगरा (वनस्पति विज्ञान विभाग) ने 01 अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार में प्रतिभाग किया। 03 विद्यार्थियों को राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप प्राप्त हुई। वर्ष 1984 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डा० हर्षवन्ती बिष्ट को उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जा चुका है।
राजकीय महिला महाविद्यालय, हल्द्वानी	<ul style="list-style-type: none"> महाविद्यालय की छात्रा कु० लतिका जोशी, बी०एस-सी०।। के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर पुरस्कार प्राप्त किया गया।
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ऋषिकेश	<ul style="list-style-type: none"> अखिल भारतीय स्तर पर एन०सी०सी० कार्यक्रम के अन्तर्गत गणतंत्र दिवस 2009 की परेड में नई दिल्ली में प्रतिभाग किया तथा अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर हेतु चयनित हुए। 04 विद्यार्थी नैट तथा 01 विद्यार्थी स्लैट परीक्षा में चयनित। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के द्वारा मंजू ठाकुर (जन्तु विज्ञान) एवं डा० आर०के० गुप्ता (वनस्पति विज्ञान) सम्मानित। डा० आर०के० उपाध्याय (भौतिकी) के द्वारा बैंकॉक (थाईलैंड) में अन्तर्राष्ट्रीय

	<p>अकादमिक भ्रमण में प्रतिभाग।</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ एन०सी०सी० के अन्तर्गत गणतंत्र परेड हेतु 06 छात्रायें एवं 05 छात्र चयनित। ■ राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय योग ओलम्पियार्ड में 05 विद्यार्थियों ने पुरुस्कार प्राप्त किये।
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार	<ul style="list-style-type: none"> ■ एम०ए० फाइनल की गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षा में श्री सन्तोष मोहन ने 73.7 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विंवि० में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ■ एन०सी०सी० के अन्तर्गत 03 छात्रों का राष्ट्रीय थल सेना कैम्प के लिए चयन तथा 08 छात्र-छात्राओं का चयन गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुआ। ■ रोवर्स रैंजर्स कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रादेशिक समागम में तृतीय स्थान प्राप्त किया। ■ राष्ट्रीय स्तर की स्पृधाओं हेतु 02 छात्रों तथा 09 छात्र-छात्राओं का नॉर्थ जोन के लिए विभिन्न स्पृधाओं हेतु चयन हुआ। ■ एन०सी०सी० के 03 कैडेट्स गणतंत्र दिवस परेड हेतु चयनित तथा 01 कैडेट ने राइट मार्कर के रूप में नेतृत्व किया तथा 03 कैडेट्स द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर थल सेना कैम्प में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व।
एम०बी० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी(नैनीताल)	<ul style="list-style-type: none"> ■ महाविद्यालय को वर्तमान पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ₹० 52.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई हैं जिसमें से ₹० 40.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। ■ महाविद्यालय को मा० वंशीधर भगत जी, परिवहन मंत्री द्वारा विधायक निधि से ₹० 5.00 लाख की धनराशि हाईटैक शौचालय तथा ₹० 20.00 लाख की धनराशि पतंजलि भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया है जिससे निर्माण कार्य प्रगति पर है। ■ वर्तमान शैक्षिक सत्र 2010–11 में एम०एस–सी० बायोटैक्नोलॉजी की कक्षायें स्ववित्त पोषित आधार पर प्रारम्भ किये जाने हेतु 30 सीट्स स्वीकृत। ■ महाविद्यालय के 22 रोवर–रेञ्जर्स ने सुनगढ़ (बागेश्वर) जाकर आपदा पीड़ितों की सहायता की। ■ महाविद्यालय के स्वर्ण जयन्ती वर्ष के उपलक्ष में दिसम्बर, 2010 में राज्य स्तरीय अन्तर महाविद्यालय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के 20 महाविद्यालयों ने प्रतिभाग किया तथा महाविद्यालय की टीम चैम्पियन रही। ■ दिनांक 01 दिसम्बर, 2010 को राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 77 स्वयंसेवी छात्र-छात्राओं ने रक्तदान किया। ■ प्रदेश के 25 महाविद्यालयों को एडूसैट से जोड़ने की प्रक्रिया के तहत एम०बी० महाविद्यालय भी एडूसैट से 29 दिसम्बर, 2010 को जुड़ गया है, जिसका शुभारम्भ देहरादून से मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। ■ महाविद्यालय के कीड़ा परिषद द्वारा इस वर्ष कुमाऊँ विश्वविद्यालय अन्तर महाविद्यालय ऐथेलिटिक्स(पुरुष) प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन मा० श्री गोबिन्द सिंह विष्ट, विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा किया गया। विश्वविद्यालय की विभिन्न अन्तर महाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में इस महाविद्यालय की टीमों ने बैडमिन्टन महिला, हाकी

	<p>महिला, बास्केटबाल(पुरुष म०) में प्रथम स्थान एवं हैण्डबॉल पुरुष में चैम्पियन रही है। इस महाविद्यालय के 30 खिलाड़ियों का अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं के लिये चयन हुआ है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ एन०सी०सी० के 6 कैडेट्स ने नई दिल्ली में आर०डी० परेड में प्रतिभाग किया, छात्रा कैडेटों ने केरल में आयोजित राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लिया। जिसमें कु० शिवानी डसेला, बी०एस-सी० प्रथम वर्ष वैस्ट कैडेट चुनी गयी। वर्ष 2010-11 से महाविद्यालय में एन०सी०सी० एयरविंग की भी स्थापना हो चुकी हैं, जिसमें 30 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। ■ महाविद्यालय में कैरयर काउन्सिलिंग के अंतर्गत प्लेसमैण्ड सैल का गठन हुआ है। प्लेसमैण्ड सैल के प्रयासों से नवम्बर, 2010 एवं दिसम्बर, 2010 में कमशः 16 एवं 22 छात्र-छात्राओं का विभिन्न संस्थानों प्लेसमेंट सम्भव हुआ है। ■ राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र-छात्राओं द्वारा आपदा पीड़ितों के लिए रु० 22700/- की धनराशि एकत्रित कर बैंक ड्राफ्ट द्वारा मा० मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजा गया। ■ एम०बी०पी०जी० कालेज, हल्द्वानी में भौतिक विज्ञान विभाग द्वारा “Recent Trends in interdisciplinary research and astrophysics space Science-3-4 N0v, 2012.
राजकीय महाविद्यालय, बलुवाकोट	<ul style="list-style-type: none"> • राजकीय महाविद्यालय बलुवाकोट- समाज शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित “Development of S.C./S.T. communities Through Govt. Policies/programmes with special reference to the state of Uttarakhand.

परिशिष्ट-10 उच्च शिक्षा विभाग के अधीन विश्वविद्यालयों की उपलब्धियाँ

दून विश्वविद्यालय, देहरादून

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12 (बी) के अंतर्गत दून विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त हुई।
- विश्वविद्यालय का प्रथम शैक्षणिक सत्र वर्ष 2009-10 में आरम्भ किया गया। वर्तमान में विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 500 छात्र-छात्रायें अध्ययनरत हैं।
- वर्तमान में प्रस्तावित 05 स्कूल यथा-प्रबन्धन स्कूल, सामाजिक विज्ञान स्कूल, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन स्कूल तथा भाषा स्कूलों के माध्यम से स्नातकोत्तर स्तर के 10 कार्यक्रम

संचालित किये जा रहे हैं। स्कूल ऑफ इन्वायरनमेन्ट एण्ड नेचुरल रिसोर्स द्वारा पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

- विश्वविद्यालय के सेन्टर फॉर पब्लिक पॉलिसी के तत्वावधान में “Regional Consultation on State Action Plan for Climate Change” विषय पर कार्यशाला सम्पन्न हुई।
- दून विश्वविद्यालय में एडू सैट के माध्यम से राज्य में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा का प्रचार-प्रसार।
- नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन (एन0टी0पी0सी0) के सौजन्य से विश्वविद्यालय में चेयर प्रोफेसर व सेन्टर फॉर पब्लिक पॉलिसी की स्थापना।
- अन्तर्गत विश्वविद्यालय युवा महोत्सव 2013 का सफलता पूर्वक आयोजन।

उराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

- पूर्व में वर्ष 2010–11 में विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या 3000 थी, जो कि वर्ष 2011–12 में बढ़कर 18000 हो गयी है।
- विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी गयी 25 एकड़ भूमि में चहारदीवारी का लगभग 85 प्रतिशत निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।
- वर्तमान में प्रदेश में 08 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 350 अध्ययन केन्द्रों पर लगभग 150 पारमपरिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
- विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों से प्राप्त उनके प्रवेश आवेदन पत्र की ऑन लाइन प्रविष्टि समय से पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराये जाने परामर्श सत्रों का निरीक्षण, परीक्षाओं के सुचारू संचालन किया जा रहा है, जो कि विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय

- विश्वविद्यालय स्तर पर किये जा रहे शोध एवं प्रसार गतिविधियों में तेजी लाने एवं समस्याओं के समाधान हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर शोध एवं प्रसार निदेशालय का गठन किया गया है तथा शोध एवं प्रसार सलाहकार समिति का भी गठन किया गया है।
- विश्वविद्यालय एवं परिसरों की सूचना एवं संचार गतिविधियों के संचालन हेतु निदेशक सूचना एवं संचार की नियुक्ति एवं विद्यार्थियों की काउन्सिलिंग एवं प्लेसमेंट गतिविधियों हेतु निदेशक काउन्सिलिंग एवं प्लेसमेंट की नियुक्ति भी की गयी है।
- विश्वविद्यालय में शिक्षण एवं शोध के उच्च मापदण्डों को विकसित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 3000 से 4000 पुस्तकों, शोध ग्रन्थों इत्यादि का डेटाबेस तैयार कर पुस्तकालय में पाठकों हेतु OPAC की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
- विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में स्थापित जिला स्तरीय Natural Resources Data Management System Centre (NRDMS) द्वारा अल्मोड़ा जनपद का 1:50,000 पैमाने पर प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का कम्प्यूटरीकृत मानचित्र एवं एकीकृत आंकड़े तैयार किये गये हैं।

- डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल के भूगोल विभाग में सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है।
- विश्वविद्यालय में दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित अकादमिक स्टाफ कॉलेज देश का 53वां तथा उत्तराखण्ड राज्य का प्रथम तथा अकेला ऐसा संस्थान है।
- विश्वविद्यालय में स्थापित महादेवी सृजन पीठ हिन्दी में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित कर रहा है।
- नये पाठ्यक्रमों में मास्टर्स ऑव विजुअल आर्ट्स, बी०लिब०, एम०लिब०, एम०फार्मा०, प्रारम्भ किये गये हैं।
- नये प्रोफेसनल पाठ्यक्रम यथा एम०सी०ए०, एम०बी०ए० इन टूरिज्म, एम०एस-सी० इन माइक्रोबाईलॉजी आदि प्रारम्भ किये गये हैं।
- विश्वविद्यालय में उत्तराखण्ड सैण्टर फॉर क्लाईमेट चेन्ज की स्थापना की गयी है जिसमें 15 विभिन्न कार्य उपखण्डों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित जानकारी एकत्र कर दुष्परिणामों के निराकरण हेतु ठोस कार्य योजना तैयार की जारही है।
- विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड स्टेट एलिजिबिलिटी टैस्ट (USET) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
- विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा हेतु परीक्षा-केन्द्र बनाया गया।
- विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर के भौतिकी विभाग द्वारा डी०एस०ए० फेज-3 पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप दिनांक 22-1-2013 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा रिव्यू कमेटी की बैठक में भौतिकी विभाग को सैन्टर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किये जाने तथा ₹० 137 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति बैठक के दौरान प्रदान की गयी है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में General Development Assistance Scheme के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में उपकरणों तथा पुस्तकों एवं जर्नल्स के क्य हेतु ₹० 2,31,56000/- की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- उत्तराखण्ड शासन द्वारा कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डी०एस०बी० परिसर में ऑडिटोरियम के निर्माण को पूर्ण करने हेतु ₹० 41.87 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है।
- विश्वविद्यालय के बायोटैक्नोलॉजी विभाग द्वारा माह जनवरी 2013 में Hands on training Programme on modern technique in Biotech. for post

graduate students/Researchers/Faculty member आयोजित किया गया, जिसमें 20 लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

- विभागाध्यक्ष बायोटैक्नोलौजी विभाग द्वारा दिनांक 03 जनवरी, 2013 से 1फरवरी, 2013 तक सीएसआईआर/आईआईटीआर लखनऊ द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार एसएफआरपी स्टार 2013 में प्रतिभाग कर शोध पत्र प्रस्तुत किया गया।
- विश्वविद्यालय के बायोटैक्नोलौजी विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा TERI, New Delhi द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी (ICOM 7) में दिनांक 6 जनवरी से 11 जनवरी 2013 तक प्रतिभाग कर एक शोधपत्र प्रस्तुत किया गया।
- विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 11वीं पंचर्षीय योनान्तर्गत छात्रा छात्रावास हेतु प्राप्त अनुदान ₹0 50.00 लाख से सोबन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा में महिला छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया।
- विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 11वीं पंचर्षीय योनान्तर्गत छात्रा छात्रावास हेतु प्राप्त अनुदान ₹0 49,71,425.00 से डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में महिला छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया।
- विश्वविद्यालय की महिला बॉक्सिंग टीम ने ऑल इण्टर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग (महिला/पुरुष) टूर्नामेंट 2012–13 जो बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर में दिनांक 27–12–2012 से 2 जनवरी, 2013 तक आयोजित की गयी में 57 से 60 कि०ग्रा० वर्ग में पिथौरागढ़ महाविद्यालय की छात्रा सुश्री मोनिला सोन ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया।
- विश्वविद्यालय की ताईक्वान्डो टीम ने अखिल भारतीय इण्टर यूनिवर्सिटी ताईक्वान्डो प्रतियोगिता जो पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ में दिनांक 21 से 25 जनवरी 2013 तक आयोजित की गयी में 57 से 60 कि०ग्रा० भार वर्ग में विश्वविद्यालय की टीम की सदस्या राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा सुश्री शालिनी सिन्हा ने कॉस्य पदक प्राप्त किया।
- विश्वविद्यालय की टेबिल टेनिस महिला टीम ने नोर्थ जोन इण्टर यूनिवर्सिटी टेबिल टेनिस (महिला/पुरुष) चैंपियनशिप जो 03 से 05 जनवरी, 2013 में आयोजित हुई में चतुर्थ स्थान प्राप्त कर अखिल भारतीय अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता 24 से 27 जनवरी, 2013 में प्रतिभाग किया।
- गणित विभाग को सैण्टर ऑव एक्सीलैंस की श्रेणी में रखा गया है।
- विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर (एम०ए०, एम०कॉम० तथा एम०एस–सी०) कक्षाओं में सैमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है।
- परीक्षा पद्धति में सुधार यथा केन्द्रीय मूल्यांकन, सत्र नियमितीकरण, परीक्षा–अवधि कम करते हुए शिक्षा सत्र पूर्णतः नियमित किया गया है।

